



नरेन्द्र कुमार पाण्डेय

अयोध्या के मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद — 2024 का लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका था , और इंडिया के घटक दलों, विपक्षी गठबंधन की गतिविधियों और घोषणाओं को देखकर तो लगता है की परिणाम को लेकर उनसे अधिक आश्रय भी कोई नहीं। लेकिन जिस गति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्राएं, उद्घाटन

और शिलान्यास कर रहे हैं, और दूरदराज की जगहों में भाषण देते घूम रहे हैं उसे देखकर मेरे मनसपटल पर प्रश्न उपजते हैं की यह मात्र 2024 का चुनाव अभियान नहीं है। मोदी-शाह की भाजपा ने इस चुनाव के नतीजे पर दस्तखत, सीलबंद करके तो मोदी-शाह की भाजपा ने तो पहले से ही अपने लॉकर में रख ही दिया है। और तैयारी 2029 के चुनाव की कर रहे हैं। इसकी वजह

चुनाव 24 में, तैयारी 29 की

और प्रमाण भाजपा के दो दिग्गज नेताओं के सार्वजनिक बयान हैं। पहले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दरभंगा में बयान देना कि देश से गरीबी मिटाने के लिए मतदाता नरेंद्र मोदी को केवल तीसरी बार नहीं बल्कि चौथी बार भी चुनने का संकल्प लें। और इसके बाद, गृह मंत्री अमित शाह षड् एक मीडिया सम्मेलन में कहना कि विपक्ष को अब 2034 के बाद के लिए अपनी तैयारी करनी चाहिए।

अब दोनों बयानों को जोड़ दीजिए तो इसका अर्थ साफ है कि 2029 में, मोदी अभूतपूर्व रूप से लगातार चौथी बार चुनाव लड़ेंगे। आपमें से जो लोग अभी भी यह माने बैठे हैं कि भाजपा में 75 की उम्र को सेवानिवृत्ति की उम्र मानने का नियम चलेगा, तो जरा गौर कर लें कि हेमा मालिनी को 75 की उम्र में मथुरा से तीसरी बार चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है। हेमा मालिनी को चुनावी टिकट साफ संकेत करता है कि 75 की उम्र को कोई 'कट-ऑफ' उम्र नहीं बनाया गया है। अगर वे इस उम्र में चुनाव लड़ सकती हैं तो 79 की उम्र में मोदी (2029 में उनकी यही उम्र होगी) चुनाव लड़ें तो भला किसे आपत्ति हो सकती है?

आप भाजपा वालों से जब इस बारे में सवाल करेंगे तो वे उल्टे आपसे यही सवाल करेंगे कि 'आपसे किसने कहा कि भाजपा में कोई उम्र सीमा तय की गई है?' वैसे भी, राजनीति में उम्र की सीमा कब लागू हुई है? मोदी आज जिस तरह से, जिन जिन जगहों में प्रचार कर रहे हैं और जो कुछ कह रहे हैं , निश्चित मानिए कि 2029 में आप मोदी को अपनी चौथी पारी के लिए चुनाव प्रचार

भाजपा जिस तरह ताबड़तोड़ गठबंधन कर रही है उस पर भी यदि गौर करें तो एक दीर्घकालिक रणनीति दिखेगी। आज भाजपा उन दलों को अपने साथ जोड़ रही है जो पहले से ही पतनशील हैं और सौदेबाजी में कमजोर पड़ते हैं, जिनके पतन को और तेज किया जा सकता है और भाजपा उनकी जगह पर काबिज हो सकती है।

करते देख सकते हैं। विचार करिए की वे तमिलनाडु और केरल को कितना समय और कितनी ऊर्जा लगा रहे हैं। नजर डालें तो उसे तमिलनाडु में अपने लिए काफी जगह बनती दिखेगी, खासतौर से इस तथ्य के मद्देनजर कि द्रविड़वाद की दूसरी दावेदार एआइडीएमके टूट चुकी है और पस्त हो चुकी है। डीएमके के नेता भी अनौपचारिक बातचीत में कबूल करते हैं कि भाजपा वहां अपने बूते भले कोई सीट न जीते मगर उसका वोट प्रतिशत काफी बढ़ सकता है। इस बार उसे भले कोई सीट न मिले मगर 2029 में खेल जरूर हो सकते हैं।

भारत में परिवार केंद्रित दलों का इतिहास कहता है कि परिवार की तीसरी

पीढ़ी तक आते-आते वे अपनी काफी शक्ति गंवा चुके होते हैं। उदाहरण के लिए आप कांग्रेस (नेहरू-गांधी परिवार) से शुरू करके बाकी दलों को इस सूची में शामिल कर सकते हैं। तो क्या उदयनिधि के नेतृत्व में डीएमके अपवाद साबित होगी?

केरल को मोदी और भाजपा दूसरे अवसर के रूप में देख रहे हैं। भाजपा और संघ जिस तरह से वहां के ईसाई समुदाय जिसका सुनिश्चित वोट कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ की राजनीति का आधार है की ओर लगातार अपना हाथ बढ़ा रही है। से यूडीएफ के दूसरे वोट बैंक, मुस्लिम समुदाय और ईसाई समुदाय के बीच संदेह कायम हो रहा है। इसे यदि कुछ ईसाई वोट भाजपा की ओर आ गए, तो मुस्लिम वोट वाम दलों की ओर मुड़ सकते हैं तब भाजपा के लिए जगह बन जाएगी। और इसी उम्मीद में मोदी वहां अपना अभियान चलाते यूए उन नेताओं को अपने साथ ले रहे हैं, जिन्हें कांग्रेस में होने की उम्मीद की जाती थी। मसलन, कांग्रेस के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों, ए.के. एंटीनी और के. करुणाकरन के क्रमशः बेटे और बेटी।

भाजपा जिस तरह ताबड़तोड़ गठबंधन कर रही है उस पर भी यदि गौर करें तो एक दीर्घकालिक रणनीति दिखेगी। आज भाजपा उन दलों को अपने साथ जोड़ रही है जो पहले से ही पतनशील हैं और सौदेबाजी में कमजोर पड़ते हैं, जिनके पतन को और तेज किया जा सकता है और भाजपा उनकी जगह पर काबिज हो सकती है। जैसे 2016 में असम गण परिषद (एजोपी) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) के साथ गठबंधन

करके चुनाव जीता, और बाद में बीपीएफ का पत्ता काट कर दूसरी जनजातीय पार्टी, प्रमोद बोरो के नेतृत्व वाली यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (यूपीपी-एल) को साथी बना लिया। 2022 में, काफी कमजोर हो चुकी बीपीएफ इस गठबंधन में वापस आई, जबकि एजोपी भी अपने मूल स्वरूप की छाया भर रह गई है। ऐसा ही बिहार में भी हुआ। भाजपा ने नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए चिराग पासवान का इस्तेमाल किया (विधानसभा चुनाव में चिराग ने खुद को मोदी जी का हनुमान बताते हुए जद-यू के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे)। और अब भाजपा जद-यू के सांसदों को तोड़ने में लगी थी, तो नीतीश के पास फिर से दलबदल करके वापस लौटने के सिवाय कोई उपाय नहीं रह गया था। जो भी हो, अगले आम चुनाव में वे और कमजोर होकर ही सामने आएंगे।

गठबंधन का यही खेल आंध्र प्रदेश और हरियाणा में भी चल रहा है। आंध्र में, कमजोर हो चुकी टीडीपी 2029 में परिवार की तीसरी पीढ़ी के नेतृत्व में और ज्यादा कमजोर हो पड़ने वाली है। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की जेजेपी तो लगभग खत्म ही हो चुकी है। तो महाराष्ट्र में भी, पुरानी सहयोगी शिवसेना दो टुकड़े हो चुके हैं और नये सहयोगी, एनसीपी से टूटे घटक का भाजपा के बिना कोई भविष्य नहीं है। इन तमाम बातों को यदि एक लड़ी में पिरोकर देखें तो स्पष्ट होता है कि मोदी-भाजपा का चुनावी अभियान 2029 के लिए शुरू हो चुका है। अब विपक्ष क्या करेगा?

2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टियां प्रभावशाली लोगों को क्यों लुभा रही हैं?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान किए। 20 श्रेणियों में 1,50,000 से अधिक नामांकन प्राप्त हुए, विभिन्न पुरस्कार श्रेणियों में डिजिटल रचनाकारों के लिए मतदान चरण में लगभग 10 लाख वोट पड़े। परिणामस्वरूप 23 विजेताओं को चुना गया, जिनमें से तीन विदेशी रचनाकार थे। श्रेणियों में रणवीर अल्लाहबादिया (जिन्हें उनके हैंडल बीयर बाइसेप्स के नाम से जाना जाता है) को प्रदान किया गया वर्ष का सर्वश्रेष्ठ व्यवधान पुरस्कार, महार कलांबे को प्रदान किया गया स्वच्छता राजदूत पुरस्कार, कविताज किशन की कविता सिंह को भोजन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्माता, कामिया जानी को सर्वश्रेष्ठ यात्रा निर्माता पुरस्कार शामिल हैं। (कर्ली टेल्स के नाम से मशहूर), सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य और फिटनेस क्रिएटर पुरस्कार अंकित बैयानपुरिया और कई अन्य को प्रदान किया गया। राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कारों की मेजबानी डिजिटल सामग्री रचनाकारों के बढ़ते प्रभाव और लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें लुभाने की भाजपा सरकार की कोशिशों



को बल देती है। जानकारों का मानना है की शल मीडिया प्रभावितों की राय को आकार देने, व्यापक दर्शकों के साथ जुड़ने और कहानियों को आगे बढ़ाने की क्षमता उन्हें हमारे अभियानों में महत्वपूर्ण बनाती है। ये लोग राजनीतिक संदेश में प्रामाणिकता और प्रासंगिकता ला सकते हैं, जनसांख्यिकी तक पहुंच सकते हैं जो पारंपरिक मीडिया कभी नहीं कर सकता।

लेकिन यह सिर्फ बीजेपी नहीं है। यहां तक कि कांग्रेस ने भी प्रभावशाली लोगों की ताकत का फायदा उठाने की कोशिश की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ट्वैल यूट्यूब कामिया

जानी को एक इंटरव्यू दिया था और इससे पहले उन्होंने यूट्यूब पर विलेज कुकिंग चैनल के साथ एक वीडियो में भी काम किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव आशीष दुआ के अनुसार, चुनाव एक युद्ध है जिसे सभी मोर्चों पर लड़ा जाना है; सोशल मीडिया एक बहुत ही दृश्यमान मोर्चा है, और विशेष रूप से ऐसे समय में जब मुख्यधारा के मीडिया ने एक कोणीय रख अपनाया है, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर इसका मुकाबला किया जाना चाहिए।

भारत में दुनिया का सबसे बड़ा YouTube ग्राहक आधार है, जहां 462 मिलियन उपयोगकर्ता इस प्लेटफॉर्म का

उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग और डिजिटल संचार चैनलों की शक्ति के कारण प्रभावशाली लोग अब आबादी के एक बड़े हिस्से तक पहुंच रहे हैं और उन्हें प्रभावित कर रहे हैं।

सोशल मीडिया के प्रभावशाली लोग प्रभावी ढंग से राय बना सकते हैं और राजनीतिक दलों के लिए समर्थन जुटा सकते हैं क्योंकि आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा युवा लोगों से बना है। हालाँकि, विशेषज्ञ राजनीतिक संदर्भ में प्रभावशाली लोगों के महत्व को बढ़ा-चढ़ाकर बताने के प्रति चेतावनी देते हैं। उनका तर्क है कि सामग्री निर्माता कथा को आकार देने और टोन सेट करने में मदद कर सकते हैं लेकिन एक बिंदु से परे चुनावों को प्रभावित नहीं कर सकते। लोग अभी भी समाचार देखेंगे, जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनका समाधान चाहेंगे और उसके आधार पर मतदान करेंगे। प्रभावशाली लोगों का प्रभाव कई अन्य कारकों से भी प्रभावित होगा, जिसमें उनकी पहुंच, विश्वसनीयता और राजनीतिक दलों द्वारा उनके साथ बातचीत करने के लिए अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण शामिल हैं।

इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा हुआ सार्वजनिक

देश की राजनीतिक पार्टियों को प्राइवेट कंपनियों से मिले चुनावी चंदा का पिटारा खुल गया, स्ट्रुद्ध ने 12 मार्च को यह आंकड़े चुनाव आयोग को मुहैया कराए थे और अब सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन से एक दिन चुनाव आयोग से यह आंकड़े अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने जो डेटा जारी किया है, वे बॉन्ड की खरीद और उनको धुनाने से संबंधित। इसमें 12 अप्रैल, 2019 से लेकर 11 जनवरी 2024 तक का डेटा है।

चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर दो लिस्ट जारी की हैं। पहली 337 पेज की लिस्ट कंपनियों की है कि उन्होंने कब कितने का बॉन्ड खरीदा। दूसरी 426 पेज की लिस्ट राजनीतिक दलों की है कि उन्होंने कब-कब कितने का बॉन्ड धुनाया।

हालाँकि यह पता नहीं कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना दान दिया था। चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को दान देने वालों में ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेधा इंजीनियरिंग, टॉरेट पावर, भारती एयरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स और वेदांता लिमिटेड शामिल हैं। इसके अलावा चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों में अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मिटल, एडलवाइस, पीवीआर, केवेंटर, सुला वाइन, वेलस्पन, सन फार्मा शामिल हैं। चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा पाने वाली पार्टियों में बीजेपी, कांग्रेस, बृहस्पति, बीआरएस, शिवसेना, टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, डीएमके, जेडीएस, एनसीपी, तृणमुखा कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, ब.क.एसपी शामिल हैं।

इसके अलावा जे-के नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेडी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, झरखू सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और जन सेना पार्टी ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा पाया है।

सबसे अधिक चुनावी चंदा देने वाली 10 कंपनियां

- फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज पीआर-रु.1,368 करोड़ के बॉन्ड खरीदे
- मेधा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड-रु.966 करोड़ के बॉन्ड खरीदे
- क्रिक सप्लाई चैन प्राइवेट लिमिटेड- रु.410 करोड़ के बॉन्ड खरीदे
- वेदांता लिमिटेड- रु.400 करोड़ के बॉन्ड खरीदे
- हल्दिया एनर्जी लिमिटेड- रु.377 करोड़ के बॉन्ड खरीदे
- एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड-रु.224 करोड़ के बॉन्ड खरीदे
- वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी- रु.220 करोड़ के बॉन्ड खरीदे
- भारती एयरटेल- रु.198 करोड़ के बॉन्ड खरीदे
- केवेंटर फूडवारक इंफ्रा लिमिटेड- रु.195 करोड़ के बॉन्ड खरीदे
- मदनलाल लिमिटेड- रु.185.5 करोड़ के बॉन्ड खरीदे

छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने अपने कंडीडेटों की घोषणा कर दी जिसमें पूर्व के 9 में से 7 सांसदों की टिकट काट दी गईं जिनमें से 4 को विधानसभा में लडवाया गया था। चूँकि छग में पार्टी ने विधानसभा चुनाव भी मोदी की गारंटी पर ही लड़ा, तो लोकसभा में स्वधिकरूप से प्रत्येक प्रत्याशी की यही सोचकर उतारा जा रहा है की जितायेंगे तो मोदी ही। जिन चार सांसदों का टिकट कटा उनमें रायपुर के सुनील सोनी की जगह बृजमोहन अग्रवाल, कांकेर से मोहन मंडवी की जगह भोजराम नाग, महासमुंद से चुन्निलाल साहू की जगह रूपकुमारी चौधरी और जांजगीर से गुहाराम अजगले की जगह कमलेश जांगडे को मौका दिया गया है। इनमें सबसे चौंकाने वाला नाम बृजमोहन अग्रवाल का है। 8 बार के विधायक एवं छग विधानसभा में भाजपा के एग्रेसिव चेहरा जिसे 'पार्टी का हनुमान' भी कहा जाता है को लेकर राजनीति के गलियारों में कई तरह की चर्चाएँ हैं कुछ का मानना है की उन्हें राज्य की राजनीति से दूर रखने का प्रयास है तो कुछ कहते हैं की वर्तमान भाजपा सरकार में कई जूनियर विधायक बड़े पोर्टफोलियो में हैं केंद्र में जाने से बृजमोहन को यहाँ की अपेक्षा कोई बड़ा

नौ में से सात की टिकट कटी, नारा एक और ग्यारह का!



पोर्टफोलियो मिल सकता है . और राज्य में अग्र अग्रवाल, राजेश मृणाल एवं अजय चंद्राकर जैसे कुछ दिग्गजों को शायद मंत्री मण्डल में जगह।

टिकट घोषणा के पूर्व चर्चा की राजनादागाव सांसद संतोष पाण्डेय की जगह पूर्व सांसद मधुसुदन यादव या अभिषेक सिंह को टिकट मिल सकती है लेकिन विधानसभा चुनाव में बस्तर के प्रभारी रहे संतोष पाण्डेय वहां के धर्मांतरण के मुद्दों पर काफी अग्रेसिव रहे और 12 में से 8 सीटें जिताने का इनाम ले गए. तो इसी मुद्दे पर विश्व हिन्दू परिषद बैक ग्राउंड के बस्तर के आदिवासी नेता महेश कश्यप को बस्तर लोकसभा से मौका मिला। भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री एवं पूर्व राज्यसभा सांसद संतोष पाण्डेय पर कोरबा से दांव खेला जा रहा है दुर्ग

मोदी मशीन में सब धुल जाता है-काँग्रेस

की राजनीति की इर्दगिर्द रहने वाली सरोज को कोरबा से उतारना अप्रत्याशित ही है क्योंकि कोरबा में विकास महती,देवेन्द्र पाण्डेय नविन पटेल, जगत बहादुर, हितानंद अग्रवाल जैसे नामों को किनारा किया गया है.एक चौकाने वाला नाम जांजगीर से कमलेश जांगडे का भी है जो एक बार जिला प्रचारित चुनाव हारने के बावजूद क्षेत्र में अपनी सक्रियता के चलते पार्टी को मजबूत करती रही और गुरुदयाल पटेल,राजेश्वर पटेल, वेदराम मनहरे,कमला पटेल,नवीन मार्कंडेय,अम्बेश जांगडे जैसे नामों की जगह आलाकमान को अपने नाम पर सहमती बनवाने में कामयाब रही। काँग्रेस से पूर्व विधायक चिंतामणी महाराज जो 2023 के विधानसभा

चुनाव से पूर्व भाजपा ज्वाइन कर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के खिलाफ टिकट की मांग की थी एवं विकास महती,देवेन्द्र पाण्डेय नविन पटेल, जगत बहादुर, हितानंद अग्रवाल जैसे नामों को किनारा किया गया है.वैसे छग में चर्चाएँ हैं की भाजपा में मात्र टिकट लाने का संघर्ष है जीत की सम्भावनाये तो प्रबल हैं। विधानसभा चुनाव हर चुकी हतोत्साहित काँग्रेस राहुल गांधी की न्याय यात्रा का माहौल छत्तीसगढ़ में बना नहीं सकी . अब जिस समय चुनाव होने है वह चैन नवरत्न का होगा राम नवमी भी होगी और हनुमान जयंती भी . ऐसे में राम मंदिर का असर स्वाभाविक रूप से छग के चुनाव में देखने को मिलेगा. इन सबके बावजूद चुनौती भाजपा के पास ही है काँग्रेस के पास

खोने को कुछ नहीं है .11 में से 9 सीटें भाजपा के पास हैं जबकि बस्तर और कोरबा दो सीटें ही काँग्रेस के पास . इन सीटों के लिए भाजपा की अत्याधिक मेहनत करने की आवश्यकता है और भाजपा संगठन के द्वारा घोषित रायपुर के उम्मीदवार का नाम यह बताने के लिए काफी है की छग में भाजपा इस बार एक भी सीट खोना नहीं चाहती .

उधर छत्तीसगढ़ में विपक्षी काँग्रेस ने सरगुजा लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार चिंतामणी महाराज को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि ई डी ने उन्हें कथित कोयला लेवी घोटाले में 'लाभार्थी' के रूप में नामित किया था, लेकिन भाजपा में शामिल होते ही उन्हें 'क्लीन चिट' मिल गई. बता दें कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले काँग्रेस के पूर्व

विधायक चिंतामणी महाराज को पिछले साल के विधानसभा चुनाव में काँग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो वो काँग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे. छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इस साल जनवरी में ईडी के एक पत्र के आधार पर कथित कोयला लेवी घोटाले में मामला दर्ज किया था, जो पिछले तीन वर्षों से इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की जांच कर रहा है. ईडी ने कथित घोटाले के 'लाभार्थी' के रूप में सामरी सीट से तत्कालीन काँग्रेस विधायक महाराज के नाम का भी उल्लेख किया. काँग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पत्र के आधार पर एसीबी ने सीट खोना नहीं चाहती .

भारतीय जनता पार्टी बड़ा प्रयोग करते हुए नजर आ रही है. बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख लिया है. इनमें सीएम विष्णुदेव साय, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई नेताओं के नाम शामिल हुए थे. छत्तीसगढ़ के इस नए ट्रेड के छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए सवाल पूछा- नीरव मोदी ललित मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, कुलदीप सेंगर, बृजभूषण शरण सिंह, अजय मिश्रा टेनी, रामदुलार गौड, चिन्मयानंद, पुलकित आर्य, IIT BHU के गुनहाार.... कुख्यात और खूंखार ये लोग भी मोदी का परिवार है ? इस मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिक्रिया दर्ज की, लेकिन आरोपी के रूप में महाराज का नाम नहीं लिया. शुक्ला ने सत्तारूढ़ दल पर हमला करते हुए टिप्पणी की, जैसे ही महाराज को मोदी वॉशिंग मशीन में डाला गया, उनके सारे पाप धुल गए। वे कमल का ताबील पहनकर ईमानदार हो गए।' अब काँग्रेस के आरोपों के बाद बीजेपी इसका कैसे जवाब देती है यह सबसे बड़ा सवाल है.

लोकसभा चुनाव से पहले

नागरिकता संशोधन कानून लागू करने को लेकर कुछ गैर-बीजेपी शासित राज्यों की ओर से विरोध किया जा रहा है. इनका कहना है कि ये अपने राज्य में सीएए लागू नहीं करने देंगे. लेकिन क्या राज्यों के पास यह अधिकार है कि सीएए को लागू होने से रोक दें. रिब्यू में इसी मुद्दे पर छपी रिपोर्ट पढ़िए. द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि नागरिकता केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है, ऐसे में राज्य सरकारों के विरोध का कोई असर नहीं होगा.

एक महीने पहले ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को अधिसूचित और लागू किया जाएगा. दिसंबर 2019 में संसद से पारित हुए इस कानून को 11 मार्च से पूरे देश में लागू कर दिया गया है. सीएए का उद्देश्य बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों सहित गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देनी है. इसे 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इस कानून के तहत, तीन पड़ोसी देशों - अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश-से आए छह अल्पसंख्यक समुदायों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इन समुदायों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं।

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू करने की घोषणा की है। इसे 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस कानून के तहत, तीन पड़ोसी देशों - अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश - से आए छह अल्पसंख्यक समुदायों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इन समुदायों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। नागरिकता संशोधन कानून लागू करने को लेकर कुछ गैर-बीजेपी शासित राज्यों की ओर से विरोध किया जा रहा है. इनका कहना है कि ये अपने राज्य में सीएए लागू नहीं करने देंगे. लेकिन क्या राज्यों के पास यह अधिकार है कि सीएए को लागू होने से रोक दें. रिब्यू में इसी मुद्दे पर छपी रिपोर्ट पढ़िए. द हिंदू की रिपोर्ट

के मुताबिक, वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि नागरिकता केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है, ऐसे में राज्य सरकारों के विरोध का कोई असर नहीं होगा. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि सीएए के तहत केंद्र सरकार ही नागरिकता देने के मामले में इंचार्ज है. राज्य स्तर की बात करें तो सिर्फ एक आमंत्रित सदस्य को ही कमिटी में जगह दी गई है. कमिटी को इस तरह से बनाया गया है कि बिना राज्य सरकार के नामित सदस्य के भी नागरिकता देने या नहीं देने पर फैसला किया जा सकता है. जिन अधिकारियों को कमिटी में जगह देने की बात कही गई है, वो सब केंद्र सरकार के ही अधिकारी होंगे. इम्पावर्ड कमिटी में इंटेलिजेंस ब्यूरो, फरिन रिजल्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (एफआरआरओ), इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर, पोस्टमास्टर जनरल... ये सब केंद्र सरकार के अधिकारी होते हैं. इसी तरह डीएलसी या जिला स्तर की कमिटी में भी सभी केंद्रीय अधिकारी होंगे.

सीएए क्या है?
नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएए) पहली बार 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने के लिए 2016 में पेश किया गया था। यह एक संयुक्त संसदीय समिति के माध्यम से पारित हुआ और 8 जनवरी, 2019 को लोकसभा द्वारा पास किया गया। हालांकि, यह 16वीं लोकसभा के भंग होने के साथ के साथ समाप्त हो गया। विधेयक को 9 दिसंबर, 2019 को 17वीं लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा फिर से पेश किया गया और 10 दिसंबर, 2019 को पास किया गया। राज्यसभा ने भी 11 दिसंबर, 2019 को विधेयक पास किया। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) 31 दिसंबर 2014 को या



सीएए लागू होने से क्या बदल जायेगा

उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले अल्पसंख्यक भारतीय नागरिकता देने के लिए पारित किया गया था। यह अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। से छह धर्मों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) के प्रवासियों पर लागू होता है। पात्र होने के लिए, व्यक्ति का पिछले 12 महीनों से लगातार और पिछले 14 सालों में से 11 सालों से भारत में निवास होना चाहिए। हालांकि, कुछ मामलों में, निवास की आवश्यकता को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद की मंजूरी मिल गई थी।

नागरिकता क्या है?
नागरिकता एक ऐसा रिश्ता है जो किसी व्यक्ति और किसी देश के बीच बनाता है। यह रिश्ता कुछ अधिकारों और कुछ जिम्मेदारियों के साथ आता है। नागरिकों को देश के कानूनों और सुरक्षा व्यवस्था का संरक्षण मिलता है। नागरिकों को देश के नेताओं को चुनने का अधिकार होता है। नागरिक को सरकारी पदों पर काम करने के मौके मिलते हैं।

भारत का संविधान पूरे भारत के लिए एक ही नागरिकता का प्रावधान करता है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में रहता है, चाहे वह किसी भी राज्य या क्षेत्र से हो, उसे भारत का नागरिक माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत, संसद को नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने का अधिकार है। इसी अधिकार के तहत, 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। यह कानून बताता है कि कौन भारत का नागरिक बन सकता है और कैसे। सातवीं अनुसूची के अनुसार, संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। 1987 तक, भारत में जन्मे किसी भी व्यक्ति को नागरिक माना जाता था। लेकिन, बांग्लादेश से अल्पसंख्यक की चिंता के कारण, कानूनों में बदलाव किया गया। इसके बाद, नागरिकता के लिए यह आवश्यक हो गया कि कम से कम माता-पिता में से एक भारतीय हो। 2004 में, कानून में और बदलाव किया गया। अब, नागरिकता के लिए यह आवश्यक है कि माता-पिता में से एक भारतीय हो। दूसरा

माता-पिता अल्पसंख्यक न हो। **भारत में अल्पसंख्यक कौन हैं?**
अल्पसंख्यक वे विदेशी होते हैं जो भारत में बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के प्रवेश करते हैं या जो वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करते हैं, लेकिन अनुमत समय अवधि से अधिक समय तक रुकते हैं। अल्पसंख्यकों को विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 के तहत जेल में डाला जा सकता है या निर्वासित किया जा सकता है। **नागरिकता प्राप्त करने के कानून क्या हैं?**
मौजूदा कानूनों के अनुसार, अल्पसंख्यक नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकते। उन्हें पंजीकरण या देशीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिक बनने से रोका जाता है। विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम ऐसे लोगों को प्रतिबंधित करते हैं और अल्पसंख्यकों को जेल या निर्वासन में डालने का प्रावधान करते हैं। **पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता-**
नागरिकता अधिनियम 1955 की

धारा 5 (ए)-भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले सात साल से भारत में सामान्य रूप से निवासी है, नागरिक बन सकता है। उन्हें नागरिकता के लिए आवेदन जमा करने से पहले लगातार 12 महीने तक भारत में रहना चाहिए। **देशीकरण के माध्यम से नागरिकता-**
नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत देशीकरण के माध्यम से भी व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसमें पात्र होने के लिए, आवेदक को पिछले 12 महीनों के दौरान, साथ ही पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्षों के दौरान भारत में रहना चाहिए। **सीएए का क्या महत्व है?**
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (सीएए) का उद्देश्य नागरिकता अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम में बदलाव करना है। यह बदलाव उन अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता प्राप्त करना आसान बनाता है जो तीन पड़ोसी देशों- बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान - के धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित हैं। **सीएए की विशेषताएं क्या हैं?**
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (सीएए) का उद्देश्य भारत के पड़ोसी देशों से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्राप्त करना आसान बनाना है। यह अधिनियम नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करता है। **यह कानून किन लोगों पर लागू होता है?**
यह कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों के उन अल्पसंख्यकों पर लागू होता है जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने पर मजबूर होना पड़ा। यह उन लोगों को अल्पसंख्यक प्रवासन की कार्यवाही से बचाने के लिए बनाया गया है। **इस कानून के तहत क्या बदलाव किए गए हैं?**
देशीकरण की आवश्यकता- इन छह धर्मों से संबंधित आवेदकों के लिए देशीकरण की आवश्यकता को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। नागरिकता के लिए कट-ऑफ

तारीख-नागरिकता के लिए कट-ऑफ तारीख 31 दिसंबर 2014 है, जिसका मतलब है कि आवेदक को उस तारीख को या उससे पहले भारत में प्रवेश करना चाहिए था। नागरिकता प्राप्त करने पर क्या होगा?
ऐसे व्यक्तियों को भारत में उनके प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक माना जाएगा। उनके अवैध प्रवास या नागरिकता के संबंध में उनके खिलाफ सभी कानूनी कार्यवाही बंद कर दी जाएगी। ओसीआई कार्ड धारकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
इस कानून में यह भी कहा गया है कि ओसीआई कार्ड रखने वाले लोग - जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को भारत में अनिश्चित काल तक रहने और काम करने की अनुमति देता है - यदि वे बड़े और छोटे अपराधों और उल्लंघनों के लिए स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं, तो वे अपना स्टेटस खो सकते हैं। **अपवाद**
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (सीएए) के तहत छूट वाले क्षेत्र नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (सीएए) कुछ क्षेत्रों को इसके प्रावधानों से छूट देता है। ये क्षेत्र हैं-
1. असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र- संविधान की छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों को सीएए से छूट दी गई है। इन क्षेत्रों में कार्बी आंगलों (असम में), गारो हिल्स (मेघालय में), चकमा जिला (मिजोरम में), और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला शामिल हैं।
2. इनर लाइन परमिट (आईएलपी) के तहत आने वाले क्षेत्र
बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के तहत आईएलपीके तहत आने वाले क्षेत्रों को भी सीएए से छूट दी गई है। **इन क्षेत्रों को छूट देने का कारण-**
इन क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों का बड़ा हिस्सा रहता है, जिनकी अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराएं हैं। सीएए को इन समुदायों के अधिकारों और पहचान को खतरे में डालने के रूप में देखा जाता है। आईएलपी क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही कानून मौजूद हैं।

इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक का चुनावी फंडिंग पर क्या असर पड़ेगा ?

शुरू से ही विवादों में घिरी केंद्र सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है. चुनावी चंदे में 'साफ-सुथरा' धन लाने और 'पारदर्शिता' बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा लाई गई इस स्कीम के तहत जनवरी 2018 और जनवरी 2024 के बीच 16,518 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए थे और इसमें से ज्यादातर राशि राजनीतिक दलों को चुनावी फंडिंग के तौर पर दी गई थी. इन बॉन्ड्स पर पारदर्शिता को लेकर कई सवाल उठ रहे थे और ये



आरोप लग रहा था कि ये योजना मनी लॉन्डरिंग या काले धन को सफेद करने के लिए इस्तेमाल हो रही थी.. साल 2018 से पहले ये चर्चा होती थी की केश से दिए गए चंदे की वजह से चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता नहीं है. इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लाते वक्त सरकार का कहना था कि ये स्कीम पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी. अब जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार दे दिया गया है तो चुनावी फंडिंग पर इसका क्या असर पड़ेगा ? आर्थिक मामलों के जानकार और जेएनयू के पूर्व प्राध्यापक प्रोफेसर अरुण

कुमार कहते हैं, 'इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म होने से चुनाव की फंडिंग पर बहुत कम फर्क पड़ता है क्योंकि चुनावी फंडिंग का ज्यादातर हिस्सा नकदी में आता है. ये फंडिंग केवल फंडिंग की पारदर्शिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है. सत्तावद्ध दल को धन मिलता रहेगा जबकि विपक्ष के धन का स्रोत कम हो जाएगा.' नितिन सेठी कहते हैं, 'मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा असर नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी देर कर दी कि तब तक सोलह हजार करोड़ रुपये कुछ सालों में ही जमा हो गए. एक 30 दिन की विंडो बची थी लोकसभा चुनाव से पहले जहाँ फिर से राजनीतिक दल फिर एक बार इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लेते. राजनीतिक दलों का नुकसान समझें तो उनका 3-4 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है.'

पांच फरवरी को वित्त मंत्रालय ने संसद में बताया कि 30 चरणों में अब तक 16,518 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए. माना जा रहा है कि इसमें से ज्यादातर बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों ने भुना लिए हैं. तो सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस स्कीम के तहत पार्टियों को इतना पैसा मिला, क्या वो पैसा वापस नहीं किया जाना चाहिए जब वो स्कीम ही रद्द कर दी गई है ? मिलन वैष्णव कहते हैं, 'सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों को उन बॉन्ड्स को वापस करने का निर्देश दिया है जिन्हें भुनाया नहीं गया है. यह उचित प्रतीत होता है. पार्टियों के लिए पहले ही खर्च किया जा चुका पैसा लौटाना मुश्किल होगा.' विशेषज्ञों का मानना है कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इलेक्टोरल बॉन्ड पर तो रोक लग गई लेकिन इन योजना की वजह से जो कथित भ्रष्टाचार हुआ है उस की तह तक पहुँचने की कोशिश अभी बाकी है.

सीएए अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने वाल अनुबंध-रिजवान पटवा

रायपुर। देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएएलागू होने पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष रिजवान पटवा ने अधिनियम को स्वागत योग्य बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शह का आभार जताया आभार जताया। पटवा ने कहा कि देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार के द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए लागू कर जनता से किया एक और

अपना बड़ा वादा पूरा कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे देश के विभाजन से कई पड़ोसी देश पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश का निर्माण हुआ और पड़ोसी देशों से अपने देश में रहनेवाले अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा करने के अनुबंध भी हुए परन्तु हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हिन्दू सिख फारसी, जैन बौद्ध को लगातार प्रताड़ित किया



जाता रहा है और वो मजहबी हिंसा एवं प्रताड़ना के शिकार होकर नारकीय जीवन जीने को

मजबूर थे। उन सभी अल्पसंख्यक हिन्दुओ को भारत की नागरिकता देकर सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देने के लिए ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए लागू करने की अधिसूचना जारी कर इसे पुरे भारत में लागू कर दिया है और इस नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए लागू होने पर हमारे पड़ोसी देश

पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि देशों से आए अल्पसंख्यक हिन्दू सिख, जैन, फारसी, बौद्ध जो 2014 से पहले से भारत में रह रहे हैं उन्हें भारत की नागरिकता देकर सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देने जा रहा है उन्होंने इस अत्यंत सराहनीय ऐतिहासिक निर्णय के लिए देश के प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह का हृदय से कोटि कोटि अभिनन्दन आभार।

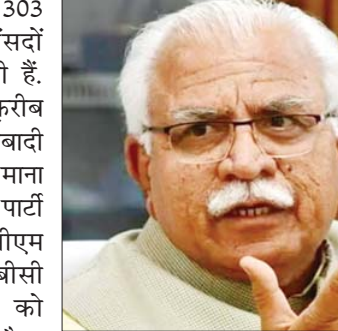
खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाने के पीछे क्या है बीजेपी की रणनीति ?



कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोते दिनों 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों में ओबीसी की भागीदारी पर बात करते दिख रहे हैं. लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी को इस संबंध में घेरती हुई नजर आती रही है. बीजेपी ने हरियाणा में मंगलवार को अहम फ़ैसला लिया मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़े के बाद जाटों के दबदबे वाले हरियाणा में बीजेपी ने अपने ओबीसी चेहरे नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री

बनाया है. ससे पहले मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव को सीएम बनाया गया था. वो भी ओबीसी समुदाय से आते हैं. ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि लोकसभा चुनावों से ठीक पहले आख़िर बीजेपी ने खट्टर को सीएम पद से क्यों हटाया और नायब सैनी को सीएम क्यों बनाया? चुनाव से पहले राज्यों में मुख्यमंत्री बदलना बीजेपी की परखी हुई रणनीति है. इसकी शुरुआत 2021 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के इस्तीफ़े से होती है. विजय रूपाणी के इस्तीफ़े के बाद पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल को बीजेपी ने गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया था. अगले साल ही यानी 2022 में गुजरात में विधानसभा चुनाव होना था.

रूपाणी की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफ़ा दे दिया था और रातोंरात मुख्यमंत्री से लेकर सीएम बनाया गया हो गया था. एक साल बाद गुजरात में चुनाव हुआ और बीजेपी ऐतिहासिक बहुमत के साथ सातवाँ बार सत्ता में लौटी थी. बीजेपी ने गुजरात के बाद कर्नाटक, उत्तराखंड और त्रिपुरा में भी मुख्यमंत्रियों को बदल दिया था. कर्नाटक को छोड़ दें तो मुख्यमंत्री बदलने की रणनीति को बीजेपी के आइने में देखा जा रहा है. बीजेपी संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस भले ओबीसी की बात कर रही है लेकिन वो हकीकत में इसे करके दिखा रही है. 77 सदस्यों वाले मोदी मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा 27 मंत्री ओबीसी हैं.



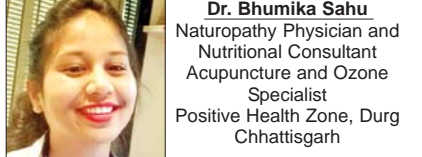
बीजेपी के 303 लोकसभा सांसदों में 85 ओबीसी हैं. हरियाणा में करीब 44 फ़ीसदी आबादी ओबीसी है. माना जा रहा है कि पार्टी सैनी को सीएम बनाकर ओबीसी मतदाताओं को लुभाना चाहती है. हरियाणा की राजनीति जाट और गैर-जाट वोट के इर्द-गिर्द घूमती है. सैनी को सीएम बनाकर बीजेपी पिछड़ी मानी जाने वाली जातियों के वोट हासिल करना चाहती है क्योंकि बीजेपी ब्राहमण, पंजाबी, बनिया और राजपूत वोटों को लेकर आश्वस्त है. बीजेपी ने पार्टी सर्वे में ये पाया कि किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के प्रदर्शन के कारण खट्टर के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है. 2019 लोकसभा चुनावों में

राज्य की 10 सीटें बीजेपी जीतने में सफल रही थी. इन चुनावों में बीजेपी को 58 फ़ीसदी वोट मिले थे और इसमें जाटों ने अहम भूमिका अदा की थी. 2019 लोकसभा चुनाव बालाकोट एयरस्ट्राइक के बाद हुए थे और बीजेपी की जीत में जानकार इस घटना को भी अहम मानते हैं. वहीं जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी का वोट शेयर घटकर 36 फ़ीसदी हो गया था. बीजेपी के हरियाणा में बदलाव करके आगामी चुनावों में खुद को मजबूत करना चाहती है.

जादुई गुणों की खान



मिट्टी में कई पोषक तत्व होते हैं, यह सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और इसमें शीतलता और अवशोषण के गुण होते हैं।



Dr. Bhumika Sahu
Naturopathy Physician and
Nutritional Consultant
Acupuncture and Ozone
Specialist
Positive Health Zone, Durg
Chhattisgarh

आयुर्वेदिक मान्यताओं के अनुसार, हमारा शरीर पांच आवश्यक तत्वों- पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से बना है। मिट्टी या मड में शरीर को अंदर से ठीक करने और किसी भी असंतुलन को ठीक करने की क्षमता होती है। प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी का उपयोग प्राचीन काल से ही कई रोगों को ठीक करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा में किया जाता रहा है। शरीर के दूषित पदार्थों को घोलकर अवशोषित कर लेती है और अंततः उन्हें शरीर से बाहर निकाल देती है।

मिट्टी में कई पोषक तत्व होते हैं, यह सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और इसमें शीतलता और अवशोषण के गुण होते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी पानी, दूध या किसी भी प्रकार का तरल पदार्थ जमीन पर गिरता है तो मिट्टी उसे सोख लेती है और जब किसी प्रकार का बीज गिरता है तो वह पेड़ या पौधा बन जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। जैसे- मैग्नीशियम, जिंक, कार्बन,

नाइट्रोजन, सल्फर, बोरान, लोहा, फास्फोरस, मैंगनीज आदि। मिट्टी के इन्हीं सभी गुणों के कारण हम इसका उपयोग थैरेपी के रूप में करते हैं जैसे मिट्टी के खान में या मिट्टी की पट्टी या पैक के रूप में, यह हमारे शरीर की गंदगी और उष्णता को अवशोषित करता है और शरीर को ठंडक प्रदान करता है। मड शरीर से खराब विषैले पदार्थों को पतला करने और अर्बजब करने का एक शक्तिशाली तरीका है।

पेट के चारों ओर मड लगाने से भी शरीर की पाचन क्रिया बेहतर होती है, साथ ही ये शरीर को प्राकृतिक रूप से डिटॉक्स करने में मदद करता है। मड शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी तेज करता है। इसके अलावा पेट के विभिन्न विकारों और डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। एसिडिटी, कब्ज, लीवर की समस्या, किडनी की समस्या, महिलाओं में मासिक धर्म की समस्या, जोड़ों में दर्द, आंखों में मिट्टी पट्टी रखने से सर दर्द, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन आदि से राहत दिलाता है। मिट्टी हमारे शरीर में रक्त संचार को बढ़ाती है और शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है और डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करती है, त्वचा संबंधी समस्याओं को दूर करता है और यह हमारी त्वचा को चमकदार भी बनाता है और हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है।

गठिया वात में हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट जरूरी



डॉ. संस्कृति सिंह
प्राकृतिक चिकित्सा
एवं आहार विशेषज्ञ
प्राज्ञीत्व हेल्थ जोन

गठिया वात (Gout) एक प्रकार का जोड़ों का दर्द है, जिससे अचानक पैर के जोड़ों (गांठ) में सूजन आ जाती है। गंभीर गाउट कभी-कभी कई जोड़ों (गांठों) को एक साथ प्रभावित कर सकता है। यह ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ने के कारण होने वाली ऐसी बीमारी है। गठिया में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जोड़ों में जमा हो जाते हैं, यह समस्या तब होती है जब शरीर में सामान्य से अधिक यूरिक एसिड बनाने लगता है। गठिया की शुरुआत सबसे पहले पैर से होती है, आमतौर पर ये पैर के अंगुठे के जोड़ों से शुरू होता है और इसमें बहुत दर्द होता है कुछ समय के बाद यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स शरीर के दूसरे जोड़ों तक भी फैल जाते हैं और यह दर्द बढ़ता हुआ कोहनी, घुटने, हाथों की अंगुलियों के जोड़ों और टिश्यू तक पहुँच जाता है। (gout) के लक्षण ज्यादातर रात में हमेशा अचानक होते हैं, अचानक जोड़ों में दर्द शुरूआत होना

- जोड़ों में सूजन आना
- प्रभावित क्षेत्र में गर्माहट महसूस होना
- जोड़ों का अकड़ जाना
- रकाल्पता (Anemia) और बुखार आना
- प्रभावित जगह को छूने पर बहुत संवेदनशील दर्द होना और
- गाउट प्रभावित जोड़ों में लाली ये लक्षण और संकेत आमतौर पर गाउट (gout) के ही होते हैं। गाउट



वहीं आयुर्वेदिक उपचार की प्रक्रिया में दोषों को संतुलित किया जाता है, जिसमें बढ़े हुए दोषों को घटाकर और हीन दोषों को बढ़ा कर रोग को मूल से समाप्त किया जाता है तथा प्राकृतिक चिकित्सा होने से इसके कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होते हैं।

समय के साथ अधिक बार भी हो सकते हैं ध्यान रखे की यदि प्रारम्भ में आपको जोड़ों (गांठ) में सूजन आती है और अचानक दर्द होता है तो यह सम्भवता गाउट (gout) का ही प्रभाव होता है। इसके शुरुआती दौर में चार से 12 घंटे के भीतर दर्द सबसे गंभीर होने की संभावना है। गाउट होने के पीछे जीवनशैली और आहार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। गठिया का मुख्य कारण अनुचित आहार होता है। जैसे अधिक मात्रा में मांस, मछली, अत्यधिक मसालेदार भोजन शराब और प्रकृतिक युक्त पेय पदार्थों का सेवन के अलावा शरीर में आई चयापचय (Metabolism) में खराबी प्रमुख है। यूरिक एसिड मूत्र की खराबी से उत्पन्न होता है और यह प्रायः रात आता है। जब कभी गुर्दे से मूत्र कम आना अथवा मूत्र अधिक बनने से सामान्य स्तर भंग होता है तो

यूरिक एसिड के क्रिस्टल भिन्न-भिन्न जोड़ों की जगह पर जमा हो जाते हैं। हमारी रक्षात्मक कोशिकाएँ इन क्रिस्टल को ग्रहण कर लेती हैं जिसके कारण जोड़ों वाली जगहों पर दर्द देने वाले पदार्थ निकलने लगते हैं। 90 प्रतिशत रोगियों में किडनी एसिड का पर्याप्त उत्सर्जन नहीं कर पाते हैं। 10 प्रतिशत से कम रोगियों में ज्यादा यूरिक एसिड बनता है। पंचकर्म के माध्यम से रोगों के मूल कारण को दूर किया जाता है। हमारे खान-पान, जीवन शैली से उत्पन्न विषाक्त द्रव्यों को बाहर निकालकर रोग का पूर्ण उपचार किया जाता है। गठिया के उपचार हेतु एलोपैथ में जिन दवाइयों का प्रयोग किया है वह एक समय के बाद शरीर पर विपरीत प्रभाव डालती है तथा पुनः गठिया होने की संभावना बनी रहती है। वहीं आयुर्वेदिक उपचार की प्रक्रिया में दोषों को संतुलित किया जाता है, जिसमें बढ़े हुए दोषों को घटाकर और हीन दोषों को बढ़ा कर रोग को मूल से समाप्त

किया जाता है तथा प्राकृतिक चिकित्सा होने से इसके कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होते हैं। हॉलिस्टिक एपरोच द्वारा उचित ट्रीटमेंट और जीवनशैली में बदलाव के साथ गाउट को प्रभावी ढंग से मैनेज किया जा सकता है। गाउट का ट्रीटमेंट आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तिगत होना चाहिए। आहार में परिवर्तन करके, हाइड्रेटेड रहकर, एवं निर्धारित दवाओं का सेवन करके, गाउट की आवृत्ति और गंभीरता को कम किया जा सकता है। यदि आप या आपका कोई परिचित गाउट से जूझ रहा है, तो पॉजिटिव हेल्थ जोन्स रायपुर में कंयुंटेरीयड मशीनों द्वारा अपनी प्रकृति एवं प्राणिक ऊर्जा के संतुलन का परीक्षण कर आवश्यकताओं के अनुरूप योग प्राणायाम ,चक्र विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा ,आहार चिकित्सा,आयुर्वेद द्वारा एक व्यापक ट्रीटमेंट किया जा रहा है

फलों का सेवन फायदेमंद तो कभी बीमारी का कारण भी



डॉ. अमित वासनिक
(Sr. Naturopathy physician)
Asha nature cure well-ness center , Bhillai , Durg , cg

एक वैज्ञानिक तथ्य है कि स्वास्थ्य और भोजन के बीच अटूट रिश्ता है। लेकिन यह रिश्ता तभी तक बना रहता है जब तक हम अपने द्वारा खाए जाने वाले आहार के प्रति सचेत रहते हैं। प्रकृति में ऐसी कई खाद्य वस्तुएं हैं जिनके बारे में उचित जानकारी न होने के कारण उसका सेवन या तो अधिक मात्रा में करते हैं या कभी करते ही नहीं। गर्मियों के सीजन में भिन्न भिन्न प्रकार के फल बाजार में उपलब्ध हैं फिर भी फरूट जूस के नाम पर अधिकांस छोटी बड़ी कंपनियां तरह तरह के प्रोडक्ट्स उपलब्ध करा रही हैं और लोग इसे खरीद भी रहे हैं। फ्रूट या फ्रूट जूस प्रकृति से जुड़ा है ये एक तरह की मानसिकता को बताता है जैसे फरूट या फरूट जूस ग्रहण करने में सेहत के लिए लाभदायक , बीमारियों को दूर रखने में मददगार होता है। बीमार व्यक्ति के लिए तो यह वरदान है। ये हमारे संस्कार में है की जब भी हम किसी बीमार से मिलने जागते हैं तो फल ले कर जाते हैं। मानव शरीर संरचना बेहद जटिल है और इसमें कई

प्रक्रियाएं एक साथ चलती रहती हैं। शरीर के संचालन के लिए पूर्ण ऊर्जा की जरूरत होती है। जब मानव शरीर बीमार पड़ता है उस वक्त उपचार के अलावा स्वस्थ आहार और फल ही हमें बीमारी से निजात दिलाते हैं। लेकिन कुछ फल कुछ विशेष व्यक्तियों के शरीर को नुकसान भी पहुंचाते हैं। हम जो भी भोजन, फल या अन्य कोई भी खाद्य

फरूटोज जो एक प्रकार है कार्बोहाइड्रेट का और जब हम इनका सेवन अधिक मात्रा में करते हैं तब फरूटोज एक नियमित मेटाबोलिक प्रक्रिया से गुजर कर हमें अंत में यूरिक एसिड नाम का प्रोडक्ट प्रदान करता है, यही यूरिक एसिड ब्लड में घुल कर hyperuricemia की कंडीशन को जन्म देता है जो हमारे शरीर के छोटे बड़े जोड़ों में जाकर जमने लगता है साथ ही दूसरे शारीरिक अंगों में जा कर गंभीर बीमारियों (अर्थराइटिस, सोरियाटिक हाइपरपलासिया, उच्च रक्तचाप , हाइपरलिपिडमिया, इन्सुलिन रेजिस्टेंस, हाइपरयुरेकेमिया ,बायोलॉजिकल स्ट्रेस, फेटी लीवर, टाईप-2 डाइबिटीज, किडनी की बिमारी, हार्ट से सम्बंधित तकलीफ) को जन्म दे रहा है

एक हार्ट पेशेंट को फरूट खाने की सलाह दी जाती है पर उसे ये नहीं बताया जाता की उसे कौनसा और कितनी मात्रा में फरूट्स लेना है इसके पीछे का विज्ञान जाने बिना लोग फ्रूट्स लेना शुरू कर देते हैं ये उतना ही खतरनाक है जितना हार्ट पेशेंट के लिए भोजन में अधिक फैट लेना. सावधान रहे गर्मियों में कही आप बिना जानकारी के अधिक मात्रा में फल तो नहीं खाने जा रहे हैं . स्वस्थ तन और मन, सुखी जीवन का आधार होता है और स्वस्थ तन और मन की चाभी हमारे स्वास्थ्य और संतुलित आहार में छुपी हुई है . स्वस्थ और ऊर्जावान रहने के लिए फल का उपयोग बेहद जरूरी है।



पदार्थ लेते है शरीर उसे एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सूक्ष्म रूप में ग्रहण करता है , हम जो कुछ खाते व पीते है शरीर उसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ,मिनिरल्स के रूप में बदल देता है, जैसा कि हम जानते है फ्रूट्स में अधिक मात्रा में

निःशुल्क नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण से कर रहे जरूरतमन्द की मदद



दुर्ग। जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। हमें अपने आपको सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि भगवान ने हमें इस लायक समझा है कि हम किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं। मनुष्य जीवन को सही ढंग से वही ईसान जीता है, जो दूसरों में खुशियां बिखेरता है। ऐसा करने से आत्मा भी खुश रहती है ऐसे ही पुण्य कार्य मे लगे है श्री राधा विनोद आश्रम बड़े कापसी के विष्णु काका व उत्तम दादा जिन्होंने अपना पूरा जीवन श्री ठाकुर जी की सेवा एवं समाज के उत्थान में लगा दिया है।उनके मार्गदर्शन में विगत 4 दशकों से निरन्तर कोयलीबेड़ा के विभिन्न क्षेत्रों में वहां के आदिवासी एवं बंगाली गाँव में लगातार स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते आ रहे है। मोशन फाउन्डेशन दुर्ग भी

समय समय पर जाकर अपनी सेवाएं देता है । फाउन्डेशन के बाँबी सिंह ने बताया कि हाल ही में हमारे फाउन्डेशन ने दृष्टि नेत्रालय और श्री राधा विनोद आश्रम बड़े कापसी पीवी 60 के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र जांच व स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन कोयलीबेड़ा के बांदे गाँव में पीवी 89 हनुमान नगर में किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में आने वाले मरीजों ने अपने आँखों की जांच कराये। जिसमें 90 मरीजों की आँखों की जांच



की गई। 11 मरीजों को मोतियाबिंद के आपरेशन की सलाह दी गई व 07 मरीजों के आँखों में छाले (प्रेटिंगियम) की शिकायत पाई गई। इन सभी मरीजों को आपरेशन की सलाह दी गई एवं 35 लोगों को चश्मा का नम्बर आया। वहीं इस शिविर में दृष्टि नेत्रालय रायपुर की मेडिकल टीम एवं मोशन फाउन्डेशन के सचिव डॉ संतोष सिंह, डॉ बिस्वास एवं श्री राधा विनोद आश्रम की मेडिकल टीम ने विशेष योगदान दिया। हमारे द्वारा केन्द्रीय जेल दुर्ग में भी निःशुल्क नेत्र जांच व बीपी जांच शिविर का आयोजन किया गया था जिसमें 210 कैदियों की आँखों की जांच की गई, 156 कैदियों को चश्मा का नम्बर आया, वहीं 9 कैदियों को मोतियाबिंद की शिकायत पाई गई । बाकी कैदियों की आँखों में सामान्य शिकायत रही जैसे आँखों में जलन, खुजली, पानी आना आदि। स्वास्थ्य शिविर में निःशुल्क सेवा देने दृष्टि नेत्रालय एवं मोशन फाउन्डेशन संतोष सिंह, बी. बाबू जी, धनंजय शुक्ला, सुधाकर सिंह, राधेश्याम चौधरी एवं केन्द्रीय जेल के डॉ एस.एस. ठाकुर का विशेष सहयोग रहा।

विश्व मानवाधिकार परिषद द्वारा मूक बधिर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण

दुर्ग। विश्व मानवाधिकार परिषद छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 14 मार्च दिन गुरुवार समय दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक सुपेला भिलाई में प्रयास श्रवण विकलांग संस्थान स्कूल प्रांगण में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया जिसमें कि कक्षा 1 से लेकर 12 वीं के मूक बधिर छात्र- छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। डॉ. संतोष सिंग जी आई स्पेशलिस्ट द्वारा आई चेकप किया गया। डॉ. राहुल सिंग जी लेप्रोस्कोपी सर्जन के द्वारा फूल बॉडी फिटनेस चेकप किया गया। विश्व मानवाधिकार परिषद



छ.ग.की टीम के सहयोग से प्रयास श्रवण विकलांग संस्थान स्कूल में मूक बधिर बच्चों की एक्टिविटी ना ही उनकी लेंग्वेज समझ आती है,हमारे डाक्टर्स द्वारा उनके हाथों की ऊंगलियों के मूवमेंट से उपचार किया बच्चों में भी काफी उत्साह रहा। खाद्य सामाग्री भी वितरण किये मूक बधिर छात्र-छात्राओं द्वारा हृदय से धन्यवाद दिये। प्रदेश अध्यक्ष कुलवंत सिंग

जी,प्रदेश अध्यक्ष मौसमी सिन्हा जी,(महिला विंग) प्रदेश मीडिया प्रभारी सरोज नागवंशी जी,प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ संतोष पांडे जी,प्रदेश सचिव आरटीआई प्रकोष्ठ किशोर कुमार जी,प्रदेश सचिव यूथ प्रकोष्ठ शैलेन्द्र पांडे जी,जिलाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ एल ज्योति जी,सीटी इनचार्ज रश्मि चतुर्वेदी जी,रायगढ़ जिलाध्यक्ष तनु डे जी,सीटी सेक्रेटरी शंकर वर्मा जी,प्राचार्य राजेश पांडे जी,अध्यापक भोज लता जी, शिक्षिका लतिका सोना जी, शिक्षक मोहम्मद शमीम जी,मौजूद रहे। अन्य शिक्षिकाएं भी उपस्थित रहीं।

Positive Health Zone
Means Complete Health
Unique Wellbeing Center

Heal & Cure

Ayurveda, Naturopathy, Mind Science, Yog, Meditation, Healing Science

Integrated Holistic Healthcare System

प्राचीन चिकित्सा प्रणाली एवं आधुनिक चिकित्सा पद्धति का वैज्ञानिक समायोजन द्वारा **बीमारियों से स्वास्थ्य की ओर एक अनूठी पहल**

High Blood Pressure, Diabetes, Fatty Liver, Heart Disease, Irritable Bowel Syndrome, Migraine, Obesity, Low Energy, High Cholesterol, Menopausal Symptom, PCOD, Thyroid, Back Pain, Allergies, Autoimmune Diseases, Metabolic Syndrome, Hormonal Problems, Mood Fluctuation, Psoriasis, Body Pain, Depression, Headache, Fibromyalgia, Spine Diseases & Many More

SERVICES

Kerala Ayurveda & Naturopathy Body Detox

Energy Healing With 3d Meditation And Chakra Vinyan

Stress Management Mind Detox

Gdv Biowell Aura & Chakra Scan

Veda Pulse - HRV Pulse Analysis Of Vata ,pitta ,kapha 5 Elements & 7 Dhatus

Diet & Lifestyle Management

Call : 9109185025, 9109185028 www.phzinfo.com

A-41, Amrapali Society, Near Ganga Diagonsti , Dhamtari Road, Pachpedi Naka, Raipur

संपादकीय



नकली दवा पर वार

देश में आए दिन नकली दवाइयों का भंडाफोड़ होना समाज के नजरिये से सुखद, पर प्रशासन के नजरिये से शर्मनाक है। सबसे दुखद है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फिर एक नकली दवा कंपनी का पकड़ा जाना। नकली दवाओं का निर्माण जिस गति से गाजियाबाद में हो रहा था, उसकी निंदा के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। यह न केवल लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, बल्कि देश के साथ शत्रुता के समान है। गाजियाबाद में पता नहीं कब से यह नकली दवा फैक्टरी चल रही थी, जहाँ रक्तचाप, मधुमेह और गैस की नकली दवाएं बनाई जा रही थीं। जाहिर है, यह कंपनी अपने बाजार प्रतिनिधियों के जोर पर अनेक चिकित्सकों को लुभावने प्रस्ताव देकर अपनी दवाओं को बेचती होगी। औषधि विभाग, क्राइम ब्रांच और पुलिस के हाथ तो महज 1.10 करोड़ रुपये की नकली दवाएं आई हैं, पर वास्तव में न जाने कितनी नकली दवाइयों की बिक्री यह कंपनी कर चुकी होगी।

खैर, नकली दवा बनाने वाले फैक्टरी संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दूसरों के लिए नजीर बन जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि मिलावटखोरों या नकली उत्पाद बनाने वाले उद्यमियों के साथ हमारे देश में ढिलाई या उदारता बरती जाती है, इसलिए अपराधियों के हौसले बुलंद रहते हैं। किसी न किसी रसूखदार का सहारा लेकर ऐसे उद्यमी-अपराधी बचने के रास्ते निकाल लेते हैं। चूंकि भारत में आबादी ज्यादा है और उसी अनुपात में बीमारियां भी हैं, तो दवाओं की मांग यहां लगातार बनी रहती है। ऐसे में, कुछ दवा निर्माता कंपनियों का काम ही यही है कि ब्रिंडेड दवाओं के नाम का लाभ उठाया जाए। दवा कारोबार में लाभ भी बहुत होता है, यह लाभ भी अपराधियों को दवा निर्माण के व्यवसाय में खींच लाता है। नकली दवाओं का मामला केवल एक राज्य या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। तेलंगाना का ताजा मामला गौर करने लायक है। तेलंगाना सरकार ने मेग लाइफ साइंसेज द्वारा निर्मित 33 लाख रुपये से ज्यादा की तीन दवाओं की जांच की है और उनमें दवा का कोई भी तत्व नहीं पाया है। राज्य के औषधि नियंत्रण प्रशासन ने कहा है कि इन तीनों नकली दवाओं में केवल चॉक पाउडर और स्टार्च मिला है। तेलंगाना में पकड़ में आई कंपनी ने कागज पर हिमाचल प्रदेश में मुख्यालय होने का दावा किया है, पर वास्तव में हिमाचल में ऐसी कोई कंपनी नहीं है। पता नहीं, ऐसी कितनी कंपनियां देश में चल रही हैं? पिछले सप्ताह ही तेलंगाना डीसीए और हैदराबाद पुलिस के संयुक्त अभियान के बाद उत्तराखंड में इसी तरह के एक नकली दवा रैकेट का भंडाफोड़ किया गया था, जिसमें चॉक पाउडर वाली नकली दवाओं को सिप्ला जैसी प्रतिष्ठित फार्मा कंपनियों की दवा के रूप में पेश किया जा रहा था। नकली दवाओं से शायद ही कोई राज्य अछूता है। पिछले महीने महाराष्ट्र में भी भारी मात्रा में नकली एंटीबायोटिक दवाओं को जब्त किया गया था। ऐसी कंपनियां अक्सर भ्रष्टाचार का सहारा लेकर सरकारी अस्पतालों में भी आपूर्ति करने में कामयाब हो जाती हैं। अब बड़ी नामी दवा कंपनियों को भी सतर्क रहना चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों और औषधि नियामक संस्थाओं के साथ मिलकर दवा की दुनिया में विश्वास सुनिश्चित करने के लिए तमाम अच्छी-सच्ची कंपनियों को एकजुट हो जाना चाहिए। देश में विष बेच रहे दवा निर्माताओं के खिलाफ जितनी सख्ती बरती जाए, उतना अच्छा है।

उपदेश से कर्म श्रेष्ठ है



गौतम बुद्ध को उनके अनुयायी यदि स्नेह से कहीं बुलाते-तो वे अवश्य जाते। फिर जब बुद्ध पहुँचते तो श्रोताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती। बुद्ध के बचनों में जो अमृतत्व होता था, उसका पान करना सभी को प्रीतिकर लगता था। उनके उपदेशों में ऐसा कुछ अवश्य होता था, जिससे गंभीर समस्याएँ सुलझ जातीं और कुछ-न-कुछ सार्थक भी प्राप्त होता। एक गरीब किसान गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और अपने गाँव आने का आग्रह किया। बुद्ध उसके .ट्ट गाँव पहुँचे तो सारा गाँव उन्हें देखने व सुनने के लिए उमड़ पड़ा, किंतु वह किसान नहीं आया। हुआ यह कि उसी दिन किसान के बैलों की जोड़ी कहीं खो गई। किसान इस दुविधा में रहा कि बुद्ध का प्रवचन सुने या अपने बैलों को खोजे ? काफी सोचने के बाद उसने अपने बैलों को खोजने का निर्णय किया। घंटों भटकने के बाद बैल मिले। थका-हारा किसान घर आया और भोजन कर सो गया। अगले दिन वह अति संकोच से क्षमाप्रार्थी बन बुद्ध के पास पहुँचा, तो वे बड़े स्नेह से बोले, मेरी दृष्टि में यह किसान मेरा सच्चा अनुयायी है। इसने उपदेश से अधिक महत्त्व कर्म को दिया। यदि यह कल बैलों को न ढूँढ़ते हुए उपदेश सुनता, तो मेरी बातें इसकी समझ में नहीं आतीं, क्योंकि मन बैलों में अटका रहता। इसने कर्म को महत्त्व देकर प्रशंसनीय काम किया। सार यह है कि हम जहाँ जिस भूमिका में हों, उसका ईमानदारी से निर्वाह करें, यही सच्ची आध्यात्मिकता है, क्योंकि प्रत्येक धर्म 'कर्म' को ही सर्वोपरि महत्त्व देता है।

भारत ने हर क्षेत्र में स्वदेशी का झंडा बुलंद किया

अनिल तिवारी

आत्मनिर्भर बनने के संकल्प पथ पर दौड़ रहे भारत ने हर क्षेत्र में स्वदेशी का झंडा बुलंद किया है। देश में इस्तेमाल होने वाले 99% मोबाइल भारत अब खुद बना रहा है, वही युद्ध पोत और हल्के लड़ाकू विमान से लेकर घातक ड्रोन तक बनाकर पूरी दुनिया में स्वदेशी गुणवत्ता का लोहा मनवाया है। अपनी स्वदेशी तकनीक के बूते चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर भारत ने न सिर्फ पूरी दुनिया को चौंका दिया बल्कि अब रक्षा उत्पादों के निर्यात का आंकड़ा 23 गुना बढ़ते हुए पहले के 686 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2022-23 में 16000 करोड़ से ऊपर करने में सफलता अर्जित की है।

केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में स्वदेशी हथियारों, उपकरणों और तकनीक के बूते आत्मनिर्भर बनने की राह पर दौड़ रहा है। स्वयंलंबी भारत अभियान के जरिए स्वदेशी सोच को मिली तरजीह के कारण ही स्वदेशी हथियारों, मिसाइल, हल्के फाइटर जेट और ड्रोन सिस्टम में दुनिया अब दिलचस्पी दिखा रही है।

आज भारत पचासी से अधिक देशों को स्वदेशी हथियार और उपकरण, कल्पजुंज निर्यात कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत और स्वयंलंबी भारत अभियान की बढौलत हथियारों के आयात पर होने वाले खर्च में भी गिरावट आई है। वर्ष 2018-19 में रक्षा क्षेत्र पर खर्च होने वाले कुल लागत में से 46% हथियारों और सिस्टम पर खर्च हुआ था। दिसंबर 2022 में यह खर्च गिरकर 35.6 प्रतिशत पर आ गया है।

भारत ने चांद पर कदम रख पूरी दुनिया को एक तरह से चौंका दिया है। शुद्ध स्वदेशी उपकरणों से लैस इसरो का चंद्रयान-3 का सफल प्रक्षेपण कर भारत दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। इसी तरह सूरज को समझने के लिए इसरो ने आदित्य

स्वदेशी तकनीक और हमारी युवा मेधा के बढौलत भारत हर दिन प्रगति की नई इबारत लिख रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नए साल में भारत अपनी आर्थिक स्थिति को और अधिक बेहतर बनाते हुए देश की विकास दर के लक्ष्य को 6.5% से आगे पहुंचाने के साथ-साथ वर्ष 2047 तक विकसित देश बनाने के लक्ष्य को पाने में कामयाब होगा।

एल-1 का सफलता पूर्वक प्रक्षेपण कर दिया है। यह देश का पहला अंतरिक्ष अभियान है जो सूर्य का अध्ययन करेगा। आदित्य एल-1 सूर्य और पृथ्वी के बीच एक खास बिंदु लैंग्रेंज पॉइंट वन जिसे एल-1 कहा जाता है, वहां स्थापित होगा। यानी सूर्य की हर गतिविधि पर नजर रखेगा। सूर्य को समझने के लिए यह यान 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा।

स्वदेशी की बढौलत भारत अंतरिक्ष की दुनिया में भी तेजी से तरक्की कर रहा है। देश का अंतरिक्ष बाजार वर्ष 2040 तक 40 से 100 अरब डॉलर के पार होने की उम्मीद है। अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन कंपनी आर्थर डी लिटिल की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। दुनिया के चार देशों ने छह मसौदे पर इसरो के साथ करार किया है। अंतरराष्ट्रीय मिशन को अंजाम देने से भारत को 14.01 करोड़ डॉलर का राजस्व मिलने की संभावना है। अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 100 से अधिक स्टार्टअप चल रहे हैं। वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी बढ़कर 10% तक होने का अनुमान है। वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष में भारत अपना स्पेस स्टेशन निर्मित कर लेगा। मालूम हो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक रक्षा उत्पादन क्षेत्र को 175000 लाख करोड़ रुपए करना है। वहीं रक्षा निर्यात को बढ़ाते हुए इसी समयवधि में 35000 करोड़ रुपए से अधिक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है।

रक्षा मंत्रालय ने 2020 में 101 रक्षा

उत्पादों के आयात पर रोक लगाई थी। यह उपकरण अब भारत में ही बन रहे हैं। 3700 रक्षा उत्पाद भारत में निर्मित किये जा रहे हैं। 2024 में और 351 सामानों का निर्माण निर्माण भारत में स्वदेशी



तकनीक से होने लगेगा। इसरो द्वारा तैयार निसार उपग्रह से समुद्र स्तर, भूजल, प्राकृतिक आपदा, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और पृथ्वी में हर घड़ी हो रहे बदलाव की जानकारी मिलने लगेगी। वर्ष 2024 के अंत तक इस मिशन को अंजाम दिया जाना है। इसरो ने वर्ष 2024 में गगनयान मानव मिशन को लॉन्च करने की योजना बनायी है। मिशन से पहले रोबोट व्योममित्रा को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। मिशन के लिए वायुसेना के चार पायलटों की पहचान सुनिश्चित कर ली गई है। भारतीय वायुसेना को इस साल फरवरी में पहला स्वदेशी फाइटर जेट तेजस एम के-1ए मिल सकता है। वायु सेवा को कुल 83 जेट मिलने हैं। इसके लिए एच ए एल से 48000 करोड़ रुपए का करार भी किया गया है।

देश में फाइव जी लांच होने के बाद सिक्स जी की तैयारी शुरू हो चुकी है।

प्रधानमंत्री ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस में कहा था कि भारत की कोशिश सिक्स जी क्षेत्र का लीडर बनने की है। स्वावलंबी भारत अभियान के कर्ताधर्ताओं का मानना है कि भारत जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और यहां की जनसंख्या जितनी है, उसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। आज भारत के लिए जितने भी आपूर्ति करता देश हैं, वे हमारी जरूरत को शायद ही पूरा कर सकते हैं। दरअसल दूसरे देशों पर निर्भर रहने की कोमत चुकानी पड़ती है जो मौजूद

दौर में हमारे देश के हित में नहीं है। रक्षा सामग्री, अनाज, कंब्यूटर, मोबाइल, कंब्यूटर ह्यूबल है या फिर ऑटोमोबाइल, हर तरफ हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। अब तक भारत जितना भी आत्मनिर्भर बना है वह मात्र असेंबलिंग के क्षेत्र में ज्यादा हुआ है। भारत को अब सही मायने में आत्मनिर्भर बनना है तो उसे कच्चे माल पर चीन या फिर किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भरता को घटानी होगी।

स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े अर्थशास्त्री प्रोफेसर अश्वनी महाजन का मानना है कि विगत कुछ वर्षों से कोशिश जरूर हो रही है और इसके नतीजे भी अच्छे आए हैं। लेकिन जरूरी है कि भारत की क्षमता को देखते हुए यहां शोध पर ज्यादा फोकस किया जाए। अभी जितने शोध हो रहे हैं वह ज्यादातर सरकारी संस्थानों या कंपनियों में हो रहे हैं। निजी क्षेत्र की

भागीदारी को इसमें बढ़ाया जाना चाहिए।

रक्षा मंत्रालय ने इस साल ऐसे सामानों की सूची जारी की है जिनका निर्माण भविष्य में देश में ही हो सकेगा। इसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर उनके आयात पर रोक लगाई जानी चाहिए। रक्षा क्षेत्र से जुड़े सैंकड़ों कल पुर्जे देश में बनने लगे हैं। इससे करोड़ों रुपए की बचत हो रही है। हर क्षेत्र के लिए स्वदेशी और आत्मनिर्भरता ही वह कुंजी है जो विश्व पटल पर भारत को आर्थिक और अंतरराष्ट्रीय मामलों में ताकतवर बना सकती है।

गौरतलब है कि नागरिकों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए देश में 160480 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों का संचालन हो रहा है। शिक्षा का बाजार जो 2020 में 180 अरब डॉलर था वर्ष 2030 तक 320 अरब डॉलर होने की संभावना है। मेक इन इंडिया के तहत देश में 34 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। केंद्र की योजना है कि वर्ष 2024 तक इनकी संख्या बढ़कर 75 किया जाना है।

स्वदेशी तकनीक और हमारी युवा मेधा के बढौलत भारत हर दिन प्रगति की नई इबारत लिख रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नए साल में भारत अपनी आर्थिक स्थिति को और अधिक बेहतर बनाते हुए देश की विकास दर के लक्ष्य को 6.5% से आगे पहुंचाने के साथ-साथ वर्ष 2047 तक विकसित देश बनाने के लक्ष्य को पाने में कामयाब होगा। इसके लिए महंगाई को नियंत्रित रखने, सरकारी कर्ज को बढ़ाने से रोकने, निर्यात बढ़ाने, व्यापार घाटा कम करने, उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के प्रयोग के साथ-साथ राष्ट्रीय चरित्र के नवनिर्माण के लिए भी मजबूत पहल करनी होगी



विकास दर के मायने

और जर्मनी सरीखे बड़े देशों से अधिक रहेगी। यह आकलन अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष का है। कुछ विदेशी अर्थशास्त्री यह आकलन कर रहे हैं कि 2024-25 के दौरान विकास दर 5 फीसदी भी रही, तो गनीमत समझें। भारत की अर्थव्यवस्था फिर भी दुनिया में सबसे आगे रहेगी। बहरहाल अर्थशास्त्री ही 8.4 फीसदी की बढ़ोतरी दर देखकर हैरान हैं, क्योंकि 30 से अधिक अर्थशास्त्रियों के अनुमान थे कि दिसंबर तिमाही में बढ़ोतरी दर 6 से 7.2 फीसदी के बीच रह सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी तीसरी तिमाही में विकास दर 6.5 फीसदी का अनुमान लगाया था, लेकिन आंकड़े तमाम अपेक्षाओं और अनुमानों को पीछे छोड़ गए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने यह पूरा डाटा जारी किया है। सभी अनिवार्य मानदंडों और क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था की गति धावक वाली है, लेकिन कृषि की अनुमानित बढ़ोतरी दर 2023-24 में 0.7 फीसदी ही रहेगी। 2022-23 में यह दर 4.7 फीसदी थी। दिसंबर तिमाही में भी कृषि की यह दर -0.8 फीसदी आंकी गई है। यह नकारात्मक और निराशाजनक संकेत है। अलबत्ता औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े खनन, उत्पादन, बिजली, गैस,

निर्माण, जल आपूर्ति आदि क्षेत्रों ने खूब गति पकड़ी है और उनकी औसतन विकास दर 9 फीसदी रहेगी। ऐसी विकास दर का सबसे बड़ा कारण यह है कि अर्थव्यवस्था में 17 फीसदी से अधिक की हिस्सेदारी रखने वाले उत्पादन क्षेत्र में 11.6 फीसदी की वृद्धि हुई है।

यही दर बीती दिसंबर तिमाही के दौरान -4.8 फीसदी, यानी नकारात्मक, थी। उत्पादन के बाद निर्माण और बिजली क्षेत्रों की वृद्धि दर क्रमशः 9.5 फीसदी और 9 फीसदी रही है। नतीजा यह है कि देश में उत्पादन और निर्माण क्षेत्रों का विकास टिकाऊ और गतिशील रहा है। सेवा क्षेत्रों-व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, वित्तीय, रियल एस्टेट, पेशेवर सेवाएं आदि-में आर्थिक विकास दर अपेक्षाकृत धीमी है, लेकिन फिर भी उन्का औसत विकास 7 फीसदी रहा है। डाटा के मुताबिक, जीडीपी का आकार 43.55 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो बीते साल की समान तिमाही में 40.35 लाख करोड़ रुपए था। बेशक जीडीपी बढ़ी है, विकास दर अप्रत्याशित रही है, गति रिन्तर है, उसके बावजूद उपभोग, खपत के स्तर पर अब भी निराशा है। बहरहाल अर्थव्यवस्था का सही फायदा तभी मिलेगा, जब

खपत और निजी निवेश में बढ़ोतरी होगी। निजी व्यय सिर्फ 3.5 फीसदी की दर से बढ़ा है। पूरे वित्त वर्ष में यह दर घटकर 3 फीसदी तक लुढ़क सकती है। हालांकि निवेश गतिविधियां 10.2 फीसदी से बढ़ती दिख रही हैं, लेकिन अर्थशास्त्री इसकी गति तेज चाहते हैं। उससे निजी उपभोग के आसार बढ़ेंगे। 2023-24 में अप्रैल-जनवरी, 2024 के दौरान देश का कर-राजस्व 18.8 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल इसी अवधि में 16.9 लाख करोड़ रुपए था। सबसिडी खाद्य, उर्वरक, यूरिया, पोषाहार और पेट्रोलियम को लेकर केंद्र सरकार की सबसिडी आगामी वर्ष 6.02 लाख करोड़ रुपए से घट कर 5.43 लाख करोड़ रुपए रह जाएगी। यानी सबसिडी पर लगातार अंकुश रखा जा रहा है। इससे भी जीडीपी में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। गौरतलब यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में यह अप्रत्याशित बढ़ोतरी और गति तब सामने आई है, जब चीन और यूरोजोन आर्थिक संकट से जुझ रहे हैं। जर्मनी में आर्थिक विकास दर -0.5 फीसदी नकारात्मक है। बहरहाल हमारी विकास दर से देश पर भरसा अधिक बढ़ेगा।

पांच फीसदी से कम 'गरीब' राष्ट्र का आधार हैं महिलाएं

कंचन शर्मा

भारत सरकार ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) का 2022-23 के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण का सारांश छपा है। औसतन भारतीय परिवार, उसके खर्च और 'गरीबी' पर यह महत्वपूर्ण आर्थिक डाटा है। नीति आयोग ने इसकी रपट जारी की है। सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि देश की आबादी के 5 फीसदी से भी कम लोग, यानी 7.20 करोड़ भारतीय ही, 'गरीब' रह गए हैं। गरीबी का यह डाटा 2011-12 के बाद सामने आया है। एक ऐसा ही सर्वेक्षण 2017-18 में भी आया था। उसमें 'गरीबी' बढ़ती हुई दिख रही थी, लिहाजा मोदी सरकार ने वह रपट छिपा ली थी। तब सरकार के आर्थिक डाटा की खूब आलोचना हुई थी। 'गरीबी' की हकीकत पर कई सवाल भी उठाए गए थे, लिहाजा 11 साल के बाद यह सर्वेक्षण विधिवत सामने आया है, जिसमें अचानक 'गरीब' की 5 फीसदी से भी कम आबादी रह गई है। यह भी निष्कर्ष सामने आया है कि ग्रामीण इलाकों में प्रति व्यक्ति माहवार खर्च 1441 रुपए है, जबकि शहरों में यही खर्च 2087 रुपए है। अब लोग गेहूं, चावल, दाल आदि अनाज पर कम खर्च करते हैं, जबकि पैकेटबंद नमकीन, चिप्स और फल आदि पर ज्यादा खर्च करते हैं। 2022-23 की रपट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में भोजन पर खर्च प्रति व्यक्ति माहवार खर्च का 46 फीसदी किया जाता है। यह खर्च 1999-00 में 59 फीसदी था। शहरों में यही औसतन खर्च 39 फीसदी है, जबकि 1999-00 में भोजन पर यही खर्च 48 फीसदी था। अब फ्रिज, टीवी,

मोबाइल आदि पर खर्च 15 फीसदी बढ़ा है। रपट स्पष्ट करती है कि औसत आय बढ़ी है, लिहाजा खर्च भी बढ़ा है, लेकिन खर्च की प्रवृत्ति और रुझान बदल गए हैं। यह सर्वेक्षण खुलासा नहीं करता कि इस अवधि में स्वरोजगार, वेतन, मजदूरी, दिहाड़ी आदि में कितनी बढ़ोतरी हुई है? आरएसएस के सरकार्यवाह (महासचिव) दत्तात्रेय होसबोले इस आकलन को सभी के सामने प्रस्तुत करते रहे हैं कि देश में 20 करोड़ लोग



गरीबी-रेखा के नीचे हैं। करीब 23 करोड़ लोग रोजाना 375 रुपए कमाने में भी असमर्थ हैं। दत्तात्रेय के खुलासे को खारिज कैसे किया जा सकता है? गरीबी के विश्लेषण में भाजपा सरकार और आरएसएस नेता के बीच यह विरोधाभास क्यों है? सवाल यह भी है कि यदि देश में 7.20 करोड़ भारतीय ही 'गरीब' रह गए हैं, तो 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज क्यों बांटा जा रहा है? अभी तो 5 साल तक यह अनाज बांटा जाना है। बीते कुछ अंतराल से प्रधानमंत्री मोदी यह भी दावा करते रहे हैं कि उनकी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को 'गरीबी' से बाहर निकाला है। 'गरीबी' के ये आंकड़े संदिग्ध लगते हैं कि न

जाने किस आधार पर 'गरीबी' तय की गई है! क्या नीति आयोग ने 'गरीबी' की परिभाषा और मानदंड तय कर लिए हैं? लिहाजा उन्हें भी सार्वजनिक किया जाए। बहरहाल सर्वेक्षण में कहा गया है कि गांवों में अनाज पर मासिक खर्च 4.91 फीसदी किया जाता है, जबकि शहरों में यह खर्च 3.52 फीसदी है। ग्रामीण दाल पर मात्र 2.01 फीसदी और शहरी 1.39 फीसदी खर्च करते हैं। भोजन के अलावा ग्रामीण परिवार अन्य वस्तुओं पर 53 फीसदी खर्च करते हैं और शहरी 60 फीसदी खर्च करते हैं। दो जून रोटी का विकल्प विलासिता वाली चीजों में ले लिया है।

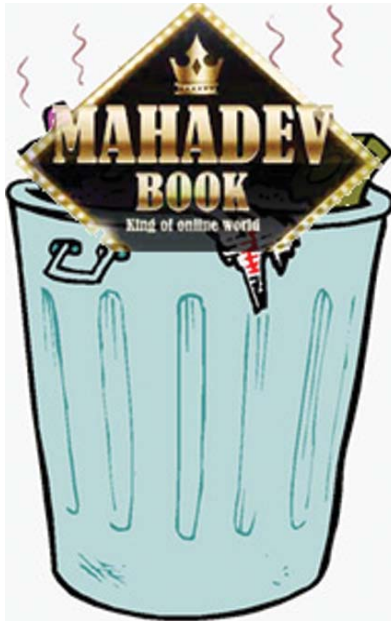
ग्रामीण इलाकों में प्रति व्यक्ति खर्च करीब 164 फीसदी बढ़ा है, जबकि शहरों में यह 146 फीसदी बढ़ गया है। मुद्रास्फीति को शामिल करके उपभोग ग्रामीण क्षेत्र में 3.1 फीसदी की बढ़ोतरी दर से बढ़ा है, जबकि शहरों में यह दर 2.7 फीसदी है। यानी गांवों में उपभोग का स्तर और गति शहरों से ज्यादा तेज है। इन 11 सालों में जीडीपी की औसत विकास दर 5.7 फीसदी रही है। भारत का उपभोग विकास देश के समस्त उत्पादन और विस्तार की तुलना में पीछे रहा है। नतीजतन किसानों सरीखे वर्गों में असंतोष देखा जा रहा है और राजनीतिक दल 'रेवडियों' बांटने में जुटे हैं। क्या अब मान लिया जाए कि जिस गरीबी को अपने कार्यकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी समाप्त नहीं कर सकीं, क्या अब उसका सफाया हो रहा है? सबसे जरूरी यह है कि सरकार उस पैमाने को सार्वजनिक करे जिसके आधार पर गरीबी परिभाषित होती है।

प्रत्येक वर्ष की भांति अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कल शुक्रवार 8 मार्च को मनाया जा रहा है। 1910 में क्लारा जेटकिन नाम की एक महिला ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बुनियाद रखी थी। वस्तुतः इस दिन को मनाने का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देते हुए उनके प्रति सम्मान, विनम्रता और आदरभाव को प्रदर्शित करना है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का मकसद महिलाओं की विभिन्न क्षेत्रों यथा आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों को मान्यता देना भी है। हर साल अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किसी न किसी थीम पर आधारित होता है और इस बार की थीम, 'इंस्पायर इंक्लूजून' है, जिसका अर्थ एक ऐसी दुनिया है, जहां हर किसी को बराबरी का हक और सम्मान मिले। भारत के संदर्भ में दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह भी है कि हमारी युवा शिक्षित बेटियां टेलीविजन/फिल्मों द्वारा परीसी जा रही अश्लीलता को निस्कोच स्वीकार कर रही हैं एवं कई प्रकार के घटिया कार्यक्रमों के निर्माण, प्रचार एवं प्रसार में बह-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आजकल फेसबुक/इंस्टाग्राम पर स्वयं लड़कियां बड़-चढ़कर अश्लीलता का प्रदर्शन करती मिल जाएंगी। अतएव इंटरनेट का अंधाधुंध सदुपयोग-दुरुपयोग युवा पीढ़ी के स्वतः अनुशासन का मामला बन चुका है। भारत की महिला साक्षरता दर विश्व के औसत 79.7 प्रतिशत से कम है। देश की आजादी के बाद से महिला साक्षरता में तेजी से वृद्धि हुई है।

जहां 1947 में कुल महिला साक्षरता दर मात्र 18 प्रतिशत थी, वह 2011 में बढ़कर 74.04 प्रतिशत हो गई थी। सकल घरेलू उत्पाद में महिलाओं के योगदान के मामले में वैश्विक औसत 37 प्रतिशत की तुलना में भारत में महिलाओं का योगदान मात्र 17 प्रतिशत है। यदि महिलाएं भी पुरुषों के समान अर्थव्यवस्था में भागीदारी करें तो इससे वर्ष 2025 तक भारत की वार्षिक जीडीपी में 2.9 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि हो सकती है। इसी तरह भारत की विधाधिकारियों में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कुल सांसदों की दस प्रतिशत भी नहीं है और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5 प्रतिशत से भी कम है। यद्यपि भारतीय संविधान में हर महिला को गरिमा और शालीनता के साथ जीने का अधिकार मिला है, तथापि महिलाओं के प्रति अत्याचारों के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।

क्या महादेव एप जाँच की रिपोर्ट का मुकाम भी रद्दी की टोकरी है

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान वाकई मोदी गारंटी है, या फिर कोई चुनावी जुमला। इसे लेकर राजनैतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मामला करीब 6000 करोड़ के महादेव ऐप बॉटिंग घोटाले का है। जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न जन सभाओं में खुला ऐलान किया था कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद महादेव ऐप घोटालेबाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लोकसभा चुनाव के पूर्व राज्य में मोदी गारंटी पर ही ग्रहण लगते नजर आ रहा है। राज्य में बीजेपी सरकार के सत्ता संभालने के तीसरे महीने में ही बड़ा उलट-फेर सामने आया है। अब श्रद्धेय सख्त निर्देशों को दरकिनार कर राज्य के EOW ने महादेव ऐप घोटाले में कारोबारी, अफसरों और सटोरियों के खिलाफ नामजद झड़कना दर्ज करते हुए सिर्फ अज्ञात के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है। राज्य सरकार के गृह मंत्रालय के इस फैसले से मोदी गारंटी पर उंगलियां उठने लगी हैं। जानकारी के मुताबिक EOW ने महादेव ऐप सट्टा घोटाले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सबको चौंका दिया है। इससे पूर्व श्रद्धेय ने आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो को शिकायती पत्र भेज कर करीब 70 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करने के निर्देश दिए



थे। सूत्रों के मुताबिक ED द्वारा जारी शिकायती पत्र में लगभग आधा दर्जन IPS अधिकारियों का काला चिट्ठा भी संलग्न किया गया था। महादेव ऐप घोटाले में नामजद के बजाए अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज करने को लेकर प्रदेश में बवाल खड़ा हो गया है। मामला EOW बनाम ED का नजर आने लगा है। बताते हैं कि गंभीर जांच के बाद ED ने नामजद आरोपियों का ब्यूरो EOW को सौंपा था। लेकिन EOW ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने से ED की कार्यवाही

सवालों के घेरे में है। दोनों ही जांच एजेंसियों में मतभेद भी दिखाई देने लगे हैं। सूत्र दावा कर रहे हैं कि नामजद FIR नहीं होने से ED की जांच रिपोर्ट विवादों में आ गई है। उनके मुताबिक मामला उच्चस्तरीय जांच के लिए CBI को सौंपा जाना चाहिए। बताते हैं कि ED ने तमाम दागी अफसरों की कार्यप्रणाली पर चोट करते हुए छत्तीसगढ़ में पुलिस सिस्टम पर गंभीर टिप्पणियां भी की थी। बताते हैं कि भ्रष्टाचार समेत IPC की दूसरी धाराओं के तहत तमाम दागियों के खिलाफ वैधानिक कदम उठाने का अनुरोध ED ने EOW से किया था। उसने नामजद FIR दर्ज करने हेतु पर्याप्त तथ्य और दस्तावेजी प्रमाण भी EOW को सौंपे थे। बावजूद इसके EOW ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। सूत्रों के मुताबिक कानून के कई सरकारी जानकारों ने भी EOW को नामजद FIR दर्ज करने की सलाह दी थी। उसे भी दरकिनार कर दिया गया, अब जानकारी सामने आ रही है कि EOW ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर ED के तथ्यों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। महादेव ऐप मामले में अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज होने से राजनैतिक गलियारा भी सक्रिय हो गया है। विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने के लिए नया हथियार मिल गया है। यह EOW में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने से ED की कार्यवाही

प्रमाणों और बयानों के आधार पर महादेव ऐप घोटाले की विभिन्न पहलुओं पर जांच की थी। इसके बाद उसने राज्य सरकार के हिस्से वाली वैधानिक कार्यवाही के लिए EOW को महत्वपूर्ण जानकारियां सौंपी थी। सूत्र बताते हैं कि जांच के उपरांत लगभग 70 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करने के लिए EOW को पर्याप्त आधार भी मुहैया कराए गए थे। बावजूद इसके अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। सरकार के इस फैसले से एजेंसियां भी सख्त में हैं। बताया जाता है कि महादेव ऐप अंतर्राज्यीय घोटाले में अब तक 1764 करोड़ रुपये जब्त किए जा चुके हैं। ED की सतत जारी कार्यवाही के बीच रायपुर में EOW में अज्ञात के खिलाफ दर्ज FIR को लेकर खलबली है। तो उधर एक बयान में राज्य के गृहमंत्री विजय शर्मा ने EOW में दर्ज FIR के मामलों को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब कहकर चौंका दिया है कि किसी के बयानों के आधार पर कोई आरोप साबित नहीं होता, इसमें और जांच की जरूरत है, बयान भर से किसी को फांसी नहीं दी जा सकती। गृहमंत्री के इस बयान की चर्चा राजनैतिक और प्रशासनिक गलियारों में भी खूब हो रही है। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच रस्साकशी देखी जा सकती है।

विधायक देवेन्द्र यादव की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज

बहुचर्चित कोल लेवी घोटाले में हैं आरोपी



छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी घोटाले के आरोपी भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेन्द्र यादव की अग्रिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई जस्टिस एन के

ये बनाये गए हैं कोल स्कैम के आरोपी
बहुचर्चित कोल लेवी घोटाला मामले में आईएएस रानू साहू, निखिल चंद्राकर के अलावा विनोद तिवारी, देवेन्द्र यादव, चंद्रदेव राय, आरपी सिंह, रोशन सिंह, पीयूष साहू, नवनीत तिवारी, मनीष उपाध्याय, नारायण साहू आरोपी बनाए गए हैं। नारायण साहू और पीयूष साहू दोनों ही सूर्यकांत तिवारी के स्टाफ हैं। रानू साहू और निखिल चंद्राकर के अलावा इनमें से किसी एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। खबर है कि इन्हें पकड़ा जा सकता है। हालांकि इन आरोपियों के वकीलों ने जमानत हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी है।

व्यास की बेंच में हुई। इससे पहले रायपुर की विशेष अदालत ने देवेन्द्र की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

कोर्ट ने माना था कि इस पूरे स्कैम से जुड़े पैसे का इस्तेमाल उन्होंने चुनाव में किया था। इसके बाद विधायक ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन उस जमानत अर्जी को आज खारिज कर दिया गया है।

पिछली सुनवाई में विधायक देवेन्द्र के वकील ने तर्क देते हुए कहा था कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत देवेन्द्र यादव के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। लिहाजा, उन्हें अपराधी नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कोर्ट से कहा कि किसी केस के आरोपी को केवल जानने से कोई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपी नहीं बनाया जा सकता।

इस केस में विधायक को सिर्फ इसलिए आरोपी बनाया गया है क्योंकि, वो सूर्यकांत

तिवारी को जानते हैं। सुनवाई के दौरान श्रद्धेय के वकील ने अग्रिम जमानत देने का विरोध किया और ED की जांच में मिले साक्ष्यों को बताया। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सोम्या चौरसिया, आईएएस रानू साहू सहित कई प्रशासनिक अधिकारी जेल में हैं-

540 करोड़ रुपये के कोल घोटाले में ईडी ने निलंबित आईएएस रानू साहू के अलावा, सोम्या चौरसिया, आईएएस समीर विश्वासी, जेडी माइनिंग एसएस नाग और कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी समेत 6 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। ये सभी ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल में हैं।

क्यों बिखर रहा INDI गठबंधन

भारत के दो दर्जन से अधिक राजनीतिक दलों ने आगामी आम चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए एक गठबंधन बनाया था। विपक्षी 26 दलों का इंडिया ब्लॉक एकजुट होने के बदले लगातार बिखर रहा है। एनसीपी में टूट से शुरू हुआ बिखराव का सफर गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार, जयंत चौधरी के बाद अब ममता बनर्जी की विदाई के साथ अनवरत जारी है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले से ही गठबंधन से किनारा करने की घोषणा कर चुके हैं।

इस गठबंधन में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के साथ-साथ तमाम क्षेत्रीय दल शामिल थे। इसका नाम 'इंडिया' गठबंधन रखा गया जिसका पूरा नाम 'इंडियन

गठबंधन से जुड़े दो अन्य दलों आम आदमी पार्टी और टीएमसी के नेता अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने भी 'इंडिया गठबंधन' से किनारा कर लिया है।

बीजेपी ने दिसंबर में ही छत्तीसगढ़, राजस्थान, और मध्य प्रदेश जैसे अहम हिंदी भाषी राज्यों के विधानसभा चुनावों में धमाकेदार अंदाज में जीत दर्ज की है। इसके बाद जनवरी में नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करके आगामी चुनाव के लिए एक तरह से बिगुल फूंक दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का एकमात्र विकल्प कांग्रेस दिखता है क्योंकि इस पार्टी की देश के लगभग हर राज्य में मौजूदगी है। कई मायनों में यही इस गठबंधन की कमजोरी का कारण भी है।

कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में सिर्फ 20 फीसदी मत

हासिल किए थे और अब भी वो सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष कर रही है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि विपक्ष की मुसीबतों के लिए महज कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। विपक्षी गठबंधन का हर दूसरा सदस्य पूरे गठबंधन के हित से पहले अपना स्वार्थ देख रहा है। क्षेत्रीय दलों को सिर्फ अपने राज्य से मतलब है। अगर ये लोग संसदीय चुनाव में हार भी जाते हैं तो उनके पास राज्य तो होगा ही। कौन किसके राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा संघर्ष इसी पर है... जानकारों का कहना है कि विपक्षी गठबंधन बीजेपी के हिंदू राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दों की काट नहीं खोज पा रहा है। विपक्षी गठबंधन में कोई वैचारिक एकरूपता नहीं है जो उन्हें एकट्ठा रख पाए...



नेशनल डेवलपमेंट इनक्लूसिव एलायंस' था। इस गठबंधन की सफलता घटक दलों के बीच एकजुटता और सीट बंटवारे से जुड़े समझौते पर टिकी थी। ताकि एक सीट पर एक उम्मीदवार उतारकर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सके। लेकिन इंडिया गठबंधन अपनी शुरुआत के छह महीने बाद ही बिखरता नजर आ रहा है। इस दिशा में सबसे ताजा झटका क्षेत्रीय नेता नीतीश कुमार हैं जिन्होंने बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। भारत की राजनीति में दलबदल कोई नया बात नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार की ओर से मिले इस झटके ने कई लोगों को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि उन्हें एक वकूत इंडिया गठबंधन के पीएम उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा था। यही काफी नहीं

होगा। विपक्षी गठबंधन का हर दूसरा सदस्य पूरे गठबंधन के हित से पहले अपना स्वार्थ देख रहा है। क्षेत्रीय दलों को सिर्फ अपने राज्य से मतलब है। अगर ये लोग संसदीय चुनाव में हार भी जाते हैं तो उनके पास राज्य तो होगा ही। कौन किसके राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा संघर्ष इसी पर है... जानकारों का कहना है कि विपक्षी गठबंधन बीजेपी के हिंदू राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दों की काट नहीं खोज पा रहा है। विपक्षी गठबंधन में कोई वैचारिक एकरूपता नहीं है जो उन्हें एकट्ठा रख पाए...

अधिकतम मतदान के जरिये ही देश की राजनीति को सुधारा जा सकता है

ललित गर्ग

अधिकतम वोटिंग का वास्तविक उद्देश्य है, जन-जन में लोकतंत्र के प्रति आस्था पैदा करना, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी निश्चित करना, वोट देने के लिए प्रेरित करना। एक जनक्रांति के रूप में 'भारतीय मतदाता संगठन' इस मुहिम के लिये सक्रिय हुआ है, यह शुभ संकेत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम से तीन माह के लिए विराम लेते हुए लोकतंत्र के महाकुंभ चुनाव में पहली बार वोटर् बनने युवाओं से रिकार्ड संख्या में मतदान का आग्रह किया। अधिकतम संख्या में मतदान लोकतंत्र की जीवन्तता का प्रमाण होने के साथ लोकतंत्र के बलशाली होने का आधार हैं और जनता की सक्रिय भागीदारी का सूचक हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या लगभग 97 करोड़ है, इनमें बड़ी संख्या युवाओं की है। इसीलिये मोदी ने मतदान में युवाओं की सक्रिय भागीदारी का आह्वान करके एक जागरूक, सक्षम एवं जुझारु राजनेता का परिचय दिया है। अधिकतम मतदान भारतीय लोकतंत्र को अधिक स्वस्थ, सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने की एक सार्थक मुहिम है। सभी मतदाताओं को मतदान के प्रति वैसा ही उत्साह दिखाना चाहिए जैसा कुछ समय से महिलाएं दिखा रही हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं से यह भी अपील की कि वे राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा बनें और राजनीतिक-चर्चाओं को लेकर जागरूक भी रहें। विशेषतः विभिन्न राजनीतिक दलों की लोकलुभावन घोषणाओं एवं चुनावी घोषणा पत्रों पर युवाओं को गहराई से जानकारी हासिल करना चाहिए कि इन घोषणाओं का आधार क्या है, इनके लिये धन कहां से आयेगा? चुनावी वैयारियों का जायजा लेने चेन्नई गए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इसी बात को उठाते हुए कहा है कि यदि राजनीतिक दलों को अपने घोषणापत्रों में लोकलुभावन वादे करने का अधिकार है तो मतदाताओं को यह जानने का हक भी है कि क्या वे वादे व्यावहारिक हैं और उन्हें लागू करने के लिए धन का प्रबंध कहां से किया जाएगा।

मिलता है। इसका कोई मतलब नहीं कि सरकारों अथवा राजनीतिक दलों के तौर-तरीकों की आलोचना तो बढ़-चढ़कर की जाए, लेकिन मतदान करने में उदासीनता दिखाई जाए। आमतौर पर मतदान न करने के पीछे यह तर्क अधिक सुनने को मिलता है कि मेरे अकेले के मत से क्या फर्क पड़ता है? एक तो यह तर्क सही नहीं, क्योंकि कई बार दो-चार मतों से भी हार-जीत होती है और दूसरे, अगर सभी यह सोचने लगे तो फिर लोकतंत्र कैसे सबल एवं सक्षम होगा? इस दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी का अधिकतम मतदान को प्रोत्साहन देने का उपक्रम एवं आह्वान एक क्रांतिकारी शुरुआत कही जा सकती है। इसका स्वागत हम इस सोच और संकल्प के साथ करें कि हमें अपने मतदान से आगामी आम चुनाव में भ्रष्टाचार, राजनीतिक अपराधीकरण एवं राजनीतिक विसंगतियों पर नियंत्रण करना है। अधिकतम मतदान के संकल्प से हमें मतदान का औसत प्रतिशत 55 से 90-95

होगा, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में यह नई जान फूंक सकती है। अब तक दुनिया के 32 देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था है लेकिन यही व्यवस्था अगर भारत में लागू हो गई तो उसकी बात ही कुछ और होगी और वह दुनिया के लिये अनुकरणीय साबित होगी। यदि ऐसा हुआ तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पुराने और सशक्त लोकतंत्रों को भी भारत का अनुसरण करना पड़ सकता है, हालांकि भारत और उनकी परिस्थितियां एक-दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। भारत में अमीर लोग वोट नहीं डालते और इन देशों में गरीब लोग वोट नहीं डालते।

भारत इस तथ्य पर गर्व कर सकता है कि जितने मतदाता भारत में हैं, दुनिया के किसी भी देश में नहीं हैं और लगभग हर साल भारत में कोई न कोई ऐसा चुनाव अवश्य होता है, जिसमें करोड़ों लोग वोट डालते हैं लेकिन अगर हम थोड़ा गहरे उतरें तो हमें बड़ी निराशा भी हो सकती है, क्या हमें यह तथ्य पता है कि पिछले 77

उत्तने ही हम भी है। यह एक त्रासदी ही है कि हम वोट मोहोत्सव को कमतर आंकते रहे हैं। जबकि आज यह बताने और जताने की जरूरत है कि इस भारत के मालिक आप और हम सभी हैं और हम जागे हुए हैं। हम सो नहीं रहे हैं। हम धोखा नहीं खा रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील करते हुए यह सही कहा कि अधिक से अधिक मतदान का मतलब एक मजबूत लोकतंत्र है और मजबूत लोकतंत्र से ही विकसित भारत बनेगा, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था एवं तकनीक विकसित करने का भी समय आ गया है जिससे अपने गांव-शहर से दूर रहने वाले वहां जाए बगैर मतदान कर सकें। ध्यान रहे कि ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में है। रोजी-रोटी के लिए अपने गांव-शहर से दूर जाकर जीवनयापन करने वाले सब लोगों के लिए यह संभव नहीं कि वे मतदान करने अपने घर-गांव लौट सकें। यदि सेना और अर्थनैतिक बलों के जवानों के साथ-साथ चुनाव ड्यूटी में शामिल लोगों के लिए वोट देने की व्यवस्था हो सकती है तो अन्य लोगों के लिए क्यों नहीं हो सकती? इस बार ऐसी किसी व्यवस्था के निर्माण के लिए निर्वाचन आयोग के साथ सरकार का भी सक्रिय होना समय की मांग है। इसी से हम अधिकतम मतदान के लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे।

अधिकतम वोटिंग का वास्तविक उद्देश्य है, जन-जन में लोकतंत्र के प्रति आस्था पैदा करना, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी निश्चित करना, वोट देने के लिए प्रेरित करना। एक जनक्रांति के रूप में 'भारतीय मतदाता संगठन' इस मुहिम के लिये सक्रिय हुआ है, यह शुभ संकेत है। इस तरह के जन-आन्दोलन के साथ-साथ भारतीय संविधान में अनिवार्य मतदान के लिये कानूनी प्रावधान बनाये जाने की तीव्र अपेक्षा है। बेल्जियम, आस्ट्रेलिया, ग्रीस, बोलिविया और इटली जैसे देशों की भांति हमारे कानून में भी मतदान न करने वालों के लिये मामूली जुर्माना निश्चित होना चाहिए।

यदि भारत में मतदान अनिवार्य हो जाए तो चुनावी भ्रष्टाचार बहुत घट जाएगा। यह भी देखा गया है कि चुनावों में येन-केन-प्रकारेण जीतने के लिये ये ही राजनीतिक दल और उम्मीदवार मतदान को बाधित भी करते हैं और उससे भी मतदान का प्रतिशत घटता है। अधिकतम मतदान से इस तरह के भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, वोट-बैंक की राजनीति थोड़ी पतली पड़ेगी। जिस दिन भारत के 90 प्रतिशत से अधिक नागरिक वोट डालने लगे, राजनीतिक जागरूकता इतनी बढ़ जाएगी कि राजनीति को सेवा की बजाय सुखों की सेज मानने वाले किसी तरह का दुस्साहस नहीं कर पायेंगे। राजनीति की सेवा या मिशन के रूप में लेने वाले ही जन-स्वीकार्य होंगे।



अधिकतम मतदान के संकल्प से हमें मतदान का औसत प्रतिशत 55 से 90-95 प्रतिशत तक ले जाना चाहिए, ताकि इस लक्ष्य को हासिल करके हम भारतीय राजनीति की तस्वीर को नया रूख दे सकें। मतदान करना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और कर्तव्य भी है, लेकिन विडम्बना है हमारे देश की कि आजादी के 77 वर्षों बाद भी नागरिक लोकतंत्र की मजबूती के लिये निष्क्रिय है। ऐसा लगता है जमीन आजाद हुई है, जमीर तो आज भी कहीं, किसी के पास गिरवी रखा हुआ है।

प्रतिशत तक ले जाना चाहिए, ताकि इस लक्ष्य को हासिल करके हम भारतीय राजनीति की तस्वीर को नया रूख दे सकें। मतदान करना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और कर्तव्य भी है, लेकिन विडम्बना है हमारे देश की कि आजादी के 77 वर्षों बाद भी नागरिक लोकतंत्र की मजबूती के लिये निष्क्रिय है। ऐसा लगता है जमीन आजाद हुई है, जमीर तो आज भी कहीं, किसी के पास गिरवी रखा हुआ है। अधिकतम मतदान की दृष्टि से नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए एक अलख जगाई थी। अनिवार्य वोट के लिये कानून लागू करना ही होगा और इस पहल के लिये सभी दलों को बाध्य होना ही

साल में हमारे यहां एक भी सरकार ऐसी नहीं बनी, जिसे कभी 50 प्रतिशत वोट मिले हों। कुल वोटों के 50 प्रतिशत नहीं, जितने वोट पड़े, उनका भी 50 प्रतिशत नहीं। गणित की दृष्टि से देखें तो 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में सिर्फ 20-25 करोड़ लोगों के समर्थन वाली सरकार क्या वास्तव में लोकतांत्रिक सरकार है? क्या वह वैध सरकार है? क्या वह बहुमत का प्रतिनिधित्व करती है? आज तक हम ऐसी सरकारों के आधीन ही रहे हैं, इसी के कारण लोकतंत्र में विषमताएं एवं विसंगतियों का बाहुल्य रहा है, लोकतंत्र के नाम पर यह छलावा हमारे साथ होता रहा है। इसके जिम्मेदार जितने राजनीति दल हैं

#SparsHTheHealingTouch

Give Yourself
A Healthy Smile & Skin

Aligners

Dental Implant

Laser Hair Reduction

Hydrafacial

Solution For all types Of Skin Problems

Dr. Vartika Sahu

MDS (Orthodontics)

Dr. Ajit Kumar

M.B.B.S., M.D. (SKIN & VD)

Banaras Hindu University

0771-4014382 / 97952-24877

BESIDE HOTEL GURU, PANDRI BUS STAND, RAIPUR (CG) 492001

समय ऐसा भी की अपने लिए समय नहीं



त्रिलोक महावर
जिंदगी में व्यस्तता अच्छी बात है। अति व्यस्त होना अच्छा भी हो सकता है और खराब भी, लेकिन अस्त-व्यस्त होना बहुत ज्यादा खतरनाक है।

अक्सर सुनने को मिलता है क्या करें हद से ज्यादा व्यस्त हैं, मरने की भी फुर्सत नहीं।

सवाल उठता है मरने की फुर्सत क्यों नहीं? जब मौत आगयी तत्काल चारा न्यारा हो जाएगा। यूँ कहिए जीने के लिए फुर्सत नहीं है। क्या जमाना आ गया खुद से बात करने तक का भी समय नहीं। अपनों से भी बात करने का समय नहीं, और तो और ढंग से किसी को सुनने का भी समय नहीं। जिंदगी घड़ी की सुईयों में घिसटती चली जा रही है। सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, लेकिन खुद से मुलाकात नहीं होती। घर में आमने-सामने बात करने की फुर्सत नहीं। हर कोई अपना अपना मोबाइल लिए बैठा है। इसी पर उंगलियाँ चल रही है। संदेश आ रहे हैं जा रहे हैं। संदेश भी कैसे संवेदना से शून्य। माना विज्ञान में तरक्की कर ली है। इंटरनेट का जमाना है। बदन दबाते ही एक कोने से दूसरे कोने तक संदेश पहुंच जाता है। लेकिन लगता है उसमें औपचारिकता कुछ ज्यादा है, और संवेदना का तो आता पता ही नहीं। किसी ने देख लिया तो अंगुठा दिखा दिया। समय कम है तो देख लिया और कोई प्रतिक्रिया नहीं की, और ज्यादा अस्त व्यस्तता है तो देखा ही नहीं। बात भी सही है क्या-क्या देखें कितना कुड़ा उड़ेलो जा रहा है। कहां तक उसमें से काम की बात तलाशें।

इससे तो अच्छा वह जमाना था। पोस्ट कार्ड का जमाना। लोग भले ही दूर-दूर रहते थे लेकिन 15 पैसे का पोस्टकार्ड उन्हें जोड़कर रखता था। बड़ी बेसब्री से डाकिए का इंतजार रहता था। छोटे

से दो पेज के पोस्टकार्ड का आधा पेज तो एड्रेस ही खा जाता था। बची खुची जगह पर मुश्किल से दिल की बात आ पाती थी। पोस्टकार्ड सुख और दुख के आँसुओं का सच्चा साक्षी होता था। कलम का जमाना गया। पोस्ट कार्ड भी किनारे हो गया। किसी कोने में पड़ा अपने पुराने दिनों को याद करता है।

अस्त व्यस्तता के इस दौर में आदमी आदमी में आदमी दूँड रहा है। कैसा जमाना आ गया प्रकृति ने तमाम नेमतेँ बख्ठी हैं। घर पहुंचते हैं तो सूरज डूब चुका होता है। उठते हैं तो पहले ही निकल चुका होता है। सुंदर आकाश, गुनगुनी धूप, चहचहाते पंखे, शांत बहती नदी, उछलते कूदते झरने, मुलायम दूब, पेड़ों की छांव, खूबसूरत फल-फूल निहारने का समय कहां हमारे पास। प्रेम में स्वार्थ का तड़का लग चुका है। जब तलक मतलब है तब तक रिश्ता है, और तभी तक प्रेम है। इसके बाद एक दूसरे को पहचानने में भी दिक्कत होती है। बदलते समय में खुद के लिए समय ना मिल पाने की हालत दिल को कचोटती है, ऐसे में मेरी ये कविता याद आती है

कैसा समय है

समय ही नहीं है
अपने लिए
बगीचे की बेंच
लंबे समय से इंतजार में है
मुदत हो गई
कोई
कविता लिखे
तितलियों को अब भी तलाश है
उस लड़के की
जो उनकी तलाश में
रहता था
सुबह सुबह बालकनी से
सूरज लौट जाता है
बैरंग
बदलाव की वजह
मौसम नहीं
कुछ से सब कुछ
हो जाने का भरम है
जिंदगी
अखबार के पहले पन्ने पर छपे
विज्ञापन सी
हो गई है



पुरुषों को खुद अपने साथ सच्चे होने, अपनी भावनाओं को स्वीकार करने की इजाजत ही नहीं है। खुद पुरुषों ने इस पैट्रीआर्कल ट्रेनिंग को इतना इंटरलाइज कर लिया है कि वो न कभी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, न दूसरों की स्वीकार करते हैं।



डॉ. नरेंद्र पाण्डेय

होलेस्टिक हेल्थ एण्ड लाइफ स्टाइल कोच
आपके जीवन में कितनी बेहद करीबी दोस्त हैं? ऐसे व्यक्ति, जिनसे आप अपने दिल की हर बात साझा कर सकते हैं? अपने किसी भी तकलीफ में जिन्हें आधी रात को आवाज दे सकें? पिछले कुछ दशकों में लोगों की सोशल लाइफ का आकार तो बढ़ा, लेकिन करीबी, पारिवारिक दोस्तियों का समूह छोटा हो चला गया। सर्वे सेंटर

ऑन अमेरिकन लाइफ की 2021 में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार 1990 में जहां 55 फीसदी पुरुषों का कहना था कि उनके जीवन में कम से कम छह बेहद करीबी दोस्त हैं। 30 साल बाद 2021 में यह संख्या घटकर 27 फीसदी हो गई। पहले जहां एक भी पुरुष ऐसा नहीं था, जिसका कोई नजदीकी, बेहद खास दोस्त न हो, अब 15 फीसदी पुरुष कह रहे थे कि उनके जीवन में एक भी करीबी दोस्त नहीं है। जिसके साथ बहुत

दुनिया में लोगों का अकेलापन बढ़ रहा है इसमें सबसे चिंतनीय बात यह है कि पुरुषों का अकेलापन महिलाओं के अकेलेपन से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। पुरुषों के बढ़ते सुसाइड रेट, ड्रग अब्यूज और हिंसा की घटनाओं के पीछे ये बढ़ता अकेलापन भी एक प्रमुख कारण है। लेकिन ऐसा क्यों है कि पुरुष महिलाओं के मुकाबले इतने ज्यादा अकेले हो गए हैं। जबकि देखा जाए तो बहुसंख्यक महिलाओं की दुनिया अब भी घर की चारदीवारी के भीतर ही कैद है। उनके मुकाबले पुरुषों के पास बाहरी दुनिया में जाने, नए लोगों से मिलने, सोशललाइज करने और दोस्तियां करने के मौके कहीं ज्यादा हैं। लेकिन फिर भी वो ज्यादा अकेले होते जा रहे हैं।

इसकी जड़ें भी कहीं पैट्रीआर्कल यानी पितृ सत्ता में ही छिपी हैं। उन पर करियर बनाने, पैसे कमाने, परिवार का भरण-पोषण करने और जीवन में सफल होने का दबाव बहुत ज्यादा है। उनके पास इतना वक्त और ऊर्जा ही नहीं है कि वह दोस्तियों में इवेंट कर सकें। वो हर दिन बिजनेस मीटिंग के लिए दसो लोगों से कैफे और बार में मिल सकते हैं, काम की बात कर सकते हैं, पैसे कमाने, जमीन खरीदने और स्टॉक मार्केट में इवेंटमेंट करने के आइडियाज बांट सकते हैं, लेकिन उनके पास किसी दोस्त के साथ बैठकर शांति से एक घंटे बतियाने, उसका हाल जानने और कुछ नहीं तो अपने मन का संगीत सुनने की भी फुर्सत नहीं है।

वक्त की कमी तो एक वजह है। लेकिन दूसरी और शायद उससे भी ज्यादा बड़ी वजह है पैट्रीआर्कल की भावना के ताकतवर होने का दबाव। पुरुष भावुक, नाजुक और कमजोर कैसे हो सकता है। वो कैसे कह सकता है कि वो थक गया है, उसे आराम चाहिए। वो अकेला है, उसे दोस्त चाहिए। उसे किसी से बात करने का मन है। वो दुखी है, उसे प्यार चाहिए। वो सेक्स डिमांड कर सकता है, लेकिन प्यार नहीं, लगाव नहीं, कोमलता और कमजोरी नहीं।

अगर उनके बीच कोई ऐसा पुरुष हो, जिसे प्यार, दोस्ती, भरोसे की जरूरत हो, जो इन नाजुक, कोमल भावनाओं को जाहिर करे तो बाकी पुरुष काफी असहज हो जाते हैं। ये जो डिस्कॉमफर्ट महसूस हो रहा होता है न, वो उनके भीतर है, उनकी दबी हुई भावनाओं से जुड़ा हुआ। लेकिन उसे स्वीकारने के लिए ताकत चाहिए। यह आसान नहीं होता। खुद को हर तरह के इमोशनल एक्सप्रेसन से दूर कर लेना या इमोशंस को ही रिजेक्ट करना।

जो वो कर रहे होते हैं, वो बाहर से देखने में तो ताकत लाती है, लेकिन यही चीज लंबे समय में उन्हें भीतर से और ज्यादा अकेला कर देती है। पुरुष का सबसे बड़ा दुख ये है कि कोई मानता ही नहीं कि ये भी कोई दुख है।

मेरे एक मित्र को कुछ दिनों से सिर में दर्द और भारीपन शिकायत थी। वह अपने पास के एक मेडिकल स्टॉर्स से कुछ दवाइयाँ लेते रहे, जब सामान्य दवाई से भी वो ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर दिया। इंटरनेट पर उन्हें सिरदर्द के लिए माइग्रेन और ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारियों तक की जानकारी मिली। इससे परेशान होकर वो एक बड़े अस्पताल दौड़ पड़े और डॉक्टर से जिल्द करके सिटी स्कैन लिखवा लिया। टेस्ट कराने पर नतीजे बिल्कुल सामान्य आए लेकिन उनका दर्द कम नहीं हो रहा 7 परेशान मेरा मित्र अब हर मिलने वालों को सलाह दे रहे हैं की यहाँ के डॉक्टर्स कुछ नहीं जानते अस्पताल बस लूटते हैं 7वैसे इंटरनेट पर बीमारी, दवाई, और टेस्ट रिपोर्टों को समझने के लिए खोजने वालों की संख्या बढ़ रही है। कई लोग अपनी बीमारी के लक्षण और इलाज की जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे हैं। वे इंटरनेट पर बीमारी के बारे में पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस पर आधारित निष्कर्ष निकालने लगते हैं। इस तरह के ज्ञान के आधार पर ही कुछ लोग डॉक्टर से इलाज कराने का भी आग्रह करते हैं।



गूगल ज्ञान चिकित्सा से डाक्टर परेशान

मरीज इंटरनेट और गूगल से जानकारी प्राप्त करके आते हैं, और फिर व्यर्थ सवाल पूछते हैं। मरीज अपनी इंटरनेट रिसर्च के आधार पर ज़िद करके टेस्ट भी करवाते हैं और बिना पर्चे की दवाइयाँ ले लेते हैं। कई लोग सीधे आकर कहते हैं कि उन्हें कैंसर हो गया है, जबकि डॉक्टर खुद कैंसर शब्द का उपयोग तब तक नहीं करते जब तक वे पूरी तरह से यकीन नहीं कर लेते कि यह कैंसर ही है, क्योंकि ऐसा कहने से मरीज को घबराहट हो सकती है।

यह दवाई क्यों लिखी है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर तो लिखा है कि यह एंटी-डिप्रेशन दवा है और मरीज को डिप्रेशन ही नहीं है। डॉक्टर ने उसे समझाया कि यह दवा सिर्फ एंटी-डिप्रेशन के लिए नहीं है और इसके अलावा भी उपयोग होती है, लेकिन इंटरनेट के ज्ञानी उस व्यक्ति को यह बात समझाना मुश्किल हो गया था। एंटी-डिप्रेशन की दुविधा वाली हो जाती है क्योंकि मरीज नकारात्मक ख्यालों से भर जाता है और इलाज देर भी हो जाती है, अक्सर मरीज दवाओं के साइड इफेक्ट्स के बारे में पढ़कर दवा लेना ही छोड़ देता है। कई बार तो वे गैरजुबुरी टेस्ट के लिए खर्चा करते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं। कई बार समझाने के बावजूद लोग यह समझने की चेष्टा नहीं करते।

इंटरनेट से जानकारी लेना सही है पर पूर्णतः भरोसा करना उचित नहीं होता क्योंकि कई बार वहाँ फर्जी दावे किए जाते हैं या गलत जानकारी फैलाई जाती है और इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। लोग सिरदर्द की समस्या के लिए इंटरनेट पर माइग्रेन और ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारियों के बारे में खोजते हैं। हालाँकि, इससे उन्हें असार्थक और गलत निष्कर्ष निकालने की भी संभावना होती है।

ब्रेन और फेफड़ों के लिए नुकसानदायक है धूमपान

हमारे दिमाग का कुल भार एक किलोग्राम से कुछ अधिक होता है। दिमाग को पूरे शरीर का मास्टरमाइंड माना जाता है। इसलिए बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को अपने दिमाग को स्वस्थ बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए।

हमारे शरीर में भले ही मस्तिष्क छोटा सा दिखने वाला अंग है। दिमाग को पूरे शरीर का मास्टरमाइंड माना जाता है। विचार, गति और भावनाओं को कंट्रोल करने के साथ ही शरीर के किस अंग को कौन सा और किस तरह से काम करना है, यह सबकुछ दिमाग ही निर्धारित करता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हमारे दिमाग का कुल भार एक किलोग्राम से कुछ अधिक होता है। लेकिन यह पावरहाउस से कम नहीं होता है।

आपको बता दें कि मस्तिष्क में अरबों तंत्रिका कोशिकाएँ होती हैं, जो सब जरूरी कार्यों को संभव बनाती हैं। मस्तिष्क की इन कोशिकाओं को न्यूरोन्स कहा जाता है। यह शरीर के बाकी हिस्सों में जानकारी भेजने का काम करती हैं। यदि दिमाग में किसी तरह की समस्या होती है, तो शरीर के सभी अंगों को मिलने वाली जानकारी में भी दिक्कत हो सकती है। यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए लगातार प्रयास करते रहने की सलाह देते हैं।

हेल्थ एक्सपर्ट्स की माँनें तो हमारे शरीर की सबसे मूल्यवान संपत्ति दिमाग है। जो शरीर के हर हिस्से को कंट्रोल करता है। लेकिन हमारी खराब लाइफस्टाइल की वजह से ब्रेन की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को अपने दिमाग को स्वस्थ बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करते

जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, तो इसका आपके दिमाग पर नकारात्मक असर पड़ता है। क्योंकि आपके दिमाग को भी आराम करने और ठीक होने के लिए कुछ समय चाहिए होता है। ऐसे में नींद पूरी न होने पर स्मृति हानि, संज्ञानात्मक गिरावट और मूड में बदलाव जैसी समस्याएँ आपको घेर सकती हैं।

धूमपान न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य बल्कि मस्तिष्क के लिए भी नुकसानदायक होता है। धूमपान करने से फेफड़ों की बीमारी होती है और ब्रेन पर भी इसका निगेटिव असर पड़ सकता है। धूमपान रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। जिसके कारण क्रोनिक इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। ऐसी स्थिति ब्रेन स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाने के साथ ही संज्ञानात्मक गिरावट की भी वजह बन सकती है। धूमपान करने वाले लोगों में डिमेंशिया रोग होने की संभावना होती है। ऐसे में आप धूमपान की आदत को छोड़कर दिमाग को स्वस्थ रख सकते हैं।

व्यायाम न करना और शारीरिक सक्रियता की कमी भी हमारे मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपकी लाइफस्टाइल गतिहीन है, तो इसके सकारात्मक बदलाव लाना जरूरी है। क्योंकि दिनभर बैठे रहना या अधिक अस्थिरता की वजह से हृदय रोग, मोटापा और मधुमेह समेत कई स्वास्थ्य समस्याएँ आपको घेर सकती हैं। यह सभी स्थितियाँ और आदतें आपके मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाती हैं। सेंडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण भी डिमेंशिया हो सकता है। ऐसे में मस्तिष्क को हेल्दी रखने के लिए रोजाना व्यायाम आदि करना चाहिए।

Dr. Bala Krishna's Advance Chest Centre

Advance Chest Clinic Offers

- Lung Cancer Screening and Treatment
- Pulmonary Function Test
- Sleep Apnea
- Asthma
- Allergy

Dr. Bala Krishna

+91 81091 61700 | Hlg 13, Laxmin Medical Hall, Shankar Nagar Main Road, Raipur, C.G.

Samarpan Hospital
Breast Care Center

Chhattisgarh 1st Breast Care Center

महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए एक समर्पित केंद्र

- ब्रेस्ट कॉस्मेटिक सर्जरी
- ब्रेस्ट दर्द
- स्तन को आकार देना
- स्तन कैंसर, कीमो थेरेपी, रेडियोथेरेपी
- स्तन संबंधी सभी समस्याएं

62682-20783, 07714-218493

Baloda Bazar road, Adarsh Nagar, Mowa, Raipur 492001

विधायकों का कम्प्यूटाइज्ड मशीन से हुआ नाड़ी परीक्षण



रायपुर। 27 फरवरी को छत्तीसगढ़ विधान सभा में माननीय विधायक गणों का नेत्र परिक्षण श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल रायपुर एवं पाजिटिव हेल्थ जोन रायपुर में उपलब्ध अति आधुनिक कम्प्यूटाइज्ड मशीन द्वारा नाड़ी परिक्षण किया गया . कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरनदास महंत एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के कर कमलो से हुआ. डॉ रामन ने कहा की इस समय समूचा विश्व आयुर्वेद की ओर देख रहा है ऐसे में इस तरह की मशीने आयुर्वेद के प्रमोशन में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगी. माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा की आयुर्वेद को बढ़ावा देना हमारी सरकार की प्रथमिकता है हमने रायपुर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के उन्नयन का कार्य प्रारम्भ करते हुए उसे 100 विस्तर क अस्पताल बनाने का कार्य प्रारम्भ किया है .

पाजिटिव हेल्थ जोन के संस्थापक/संचालक डॉ. अनिल गुप्ता ने जानकारी दी की जिस तरह आधुनिक चिकित्सा पद्धति में बीमारी का पता कुछ लैब टेस्ट और जांचों की मदद से लगाया जाता है। उसी तरह आयुर्वेद में भी बीमारी की पहचान करने के कई तरीके हैं। इनमें नाड़ी परीक्षण प्रमुख है। इसमें मरीज की नाड़ी की गति नापकर बीमारियों का पता लगाया जाता है। यहाँ पर कॉम्प्युटराइज्ड मशीन द्वारा HRV के माध्यम से हृदय की गति के प्रभाव को मापते हुए

भविष्य में शरीर में आने वाली बीमारियों का अनुमान लगाया जा सकता है। पाजिटिव हेल्थ जोन के कार्डिनेटर डॉ. नरेंद्र पाण्डेय ने बताया की आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति की प्रारम्भिक संरचना को प्रकृति कहा जाता है व्यक्ति के स्वास्थ्य संदर्भित व्यक्तिगत प्रकृति की जानकारी महत्वपूर्ण होती है. किसी भी व्यक्ति के उच्चतम स्वास्थ्य को समझने के लिए उस व्यक्ति की प्रकृति को जानना अति आवश्यक है.

रायपुर स्थित पाजिटिव हेल्थ जोन में एक अति आधुनिक मशीन है जिसके द्वारा व्यक्ति के त्रिदोष की स्थिति, सप्त रसायनों एवं पंच महाभूतों का विश्लेषण प्राप्त किया सकता है . उक्त मशीन से व्यक्ति विशेष के ओजस, तेजस एवं प्राण की विश्लेशनात्मक जानकारी भी

